सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 267, नई दिल्ली । शुक्रवार, 06 दिसम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे।

03 वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल में डेक्सा स्कैन सुविधा का उद्घाटन
06 चिकित्सा में आत्मनिर्भरता के कदम
08 ओडिशा में सोने का खदानें, ओडिशा के दो जिलों में सोने की खदानें मिली हैं

पाबंदियों पर ढील देने को राजी हुई सुप्रीम कोर्ट

संजय बाटला

पॉल्यूशन बढ़ा तो सख्ती बढ़ा दें, सभी मजदूरों को 8 हजार के हिसाब से हर्जाने की राशि दें।

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने दिल्ली में ग्रेप IV की पाबंदियों में ढील देकर ग्रेप 2 की पाबंदियों को लागू रखने के लिए कहा।

एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने कोर्ट को कहा की दिल्ली की हवा यूरोप जैसी नहीं हो सकती।

सीएक्युएम ने कोर्ट को बताया दिल्ली के एक्यूआई लेवल में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव हो रहे हैं। दिल्ली में नवंबर-दिसंबर में हमेशा ऐसे ही हाल रहते हैं। हमारे वातावरण और मौसम के हिसाब से हमारे यहां की हवा यूरोपीय देशों जैसी नहीं हो सकती। इसलिए एक्यूआई लेवल के हिसाब से ही ग्रैप रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएं। अगले एक हफ्ते के एक्यूआई अनुमान के हिसाब से हम ग्रैप 2 लेवल की पाबंदियां लगाने का सुझाव देते हैं।

सीएक्युएम की बातों पर कोर्ट अमिकस अपराजिता सिंह ने कहा कि हम नहीं मानते कि दिल्ली में प्रदूषण के हालात और नहीं सुधर सकते। यह कार्यान्वयन की समस्या को दर्शाता है। ग्रैप 4 की ग्राउंड लेवल रियलिटी चैक करनी होगी। कई चीजें सिर्फ कागजों पर है। दिल्ली में अभी भी कचरे को खुले में जलाया जा रहा है। हम ग्रैप 4 से बाहर आ सकते हैं लेकिन कमीशन को इसमें सहयोग करना होगा और योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से करना होगा। कोर्ट ने कहा कि अभी और मॉनिटरिंग की जरूरत है और इसलिए हम कमीशन को ग्रेप IV की जगह ग्रैप 2 लागू करने की इजाजत देते हैं और सलाह देते है की बेहतर होगा कमीशन ग्रैप 3 की भी कुछ जरूरी पाबंदियों को अभी लगाए रखें।

कोर्ट ने साथ ही कहा अगर एक्यूआई 350 के पार जाता है तो तुरंत ग्रैप 3 की पाबंदियां लगाई जाएं। ऐसे ही 400 पार जाने पर ग्रैप 4 की पाबंदियां फिर से लगाई जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू रहने के दौरान मजदूरों को दिए गए हर्जाने को लेकर चार राज्यों से जानकारी ली। जिस पर दिल्ली सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने कहा कि हमने 90 हजार मजदूरों को 2 हजार का भुगतान किया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि 90 हजार मजदूर 8 हजार रुपए के हकदार हैं। आप बचे हुए 6 हजार कब तक देंगे ? क्या आप मजदूरों को भूखा रखना चाहते हैं ? हम कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर रहे हैं। इसके जवाब में दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने कोर्ट को बताया की हम कल ही हर्जाने के बकाया राशि का भुगतान कर देंगे।

जस्टिस ओका ने जानना चाहा की क्या दिल्ली में क्या सिर्फ 90 हजार मजदूर हैं ? इस पर दिल्ली के मुख्य सचिव ने बताया की पोर्टल पर 90693 हजार पंजीकृत मजदूर हैं।

इस पर जस्टिस ओका ने जानना चाहा की जो मजदूर पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है उन्हें ढूंढने के लिए सरकार क्या कोई कोशिश नहीं करेगी, और ना ही कोई यह देखेगा की उनका भुगतान हो रहा है या नहीं ?

क्या यही आपका अप्रोच है तो बताए जो मजदूर पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए आपने क्या किया ?

इसके बाद जस्टिस ओका ने बाकी राज्यों से मुआवजे की डिटेल मांगी तो राजस्थान सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि एनसीआर रीजन में राजस्थान के दो जिले हैं जिसमें 3526 मजदूर हैं। इनमें से 2062 मजदूरों का भुगतान हो गया है। टोटल अमाउंट- 76 लाख 59 हजार रुपए है। बचा हुआ भुगतान हम 1 से 2 दिन में कर देंगे और हमने और लेबर इंस्पेक्टर भी अपॉइंट किए हैं।

हरियाणा सरकार ने बताया एनसीआर रीजन हरियाणा में 2 लाख 57 हजार मजदूर हैं। इनमें से 1 लाख 6 हजार मजदूरों को भुगतान हो चुका है अन्य सभी मजदूरों को मैसेज भेजा जा चुका है।

उत्तर प्रदेश ने बताया की एनसीआर रीजन यूपी में मजदूरों के लिए 97 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है और 4,88,246 मजदूरों में से 8,046 मजदूरों को भुगतान किया जा चुका है।

ग्रेप क्या है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को ग्रेप कहा जाता है। यह आपातकालीन प्रोटोकॉल का एक सेट है, जो तब सक्रिय होता है जब प्रदूषण का स्तर खतरनाक मानकों तक पहुंच जाता है।

अभी दिल्ली में एयर पॉल्यूशन ग्रेप 2 के तहत क्या क्या पाबंदी लागू रहेगी, जाने!

1. होटल- रेस्टोरेंट में लकड़ी-कोयला जलाने पर रोक
2. पेट्रोल-डीजल की पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध
3. ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग और फैक्ट्रियां बंद
4. कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट बंद
5. कंस्ट्रक्शन से जुड़े ज्यादातर कामों पर रोक
6. कोयले के इस्तेमाल और खुले में कूड़ा जलाने पर पाबंदी
7. बच्चों की सेहत को देखते हुए स्कूल-कॉलेज बंद किए जा सकते हैं
8. प्राइवेट व्हीकल की जगह पब्लिक व्हीकल से चलने की एडवाइजरी।

क्या कैश लेन-देन अब अपराध बन चुका है ? नए इनकम टैक्स नियमों ने आम आदमी को मुश्किल में डाला

इशिका मुख्य रिपोर्टर रांची झारखंड
परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। क्या 10,000 से अधिक के कैश लेन-देन पर पेनल्टी लगाना वाकई आम लोगों की भलाई के लिए है, या यह सरकारी नियंत्रण की एक और कड़ी है? भारत में इनकम टैक्स विभाग ने कैश लेन-देन को लेकर इतने सख्त नियम लागू कर दिए हैं कि आम आदमी हर कदम पर कानून के जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा है।

क्या हैं ये नियम, जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं?*

1. * 10,000 से अधिक के व्यवसाय खर्च पर प्रतिबंध:*

यदि आप व्यवसाय के लिए 10,000 से अधिक का भुगतान कैश में करते हैं, तो यह नियमों के खिलाफ है। क्या यह छोटे व्यवसायियों के लिए एक और मुश्किल पैदा नहीं कर रहा है?

2. *शादी और बड़े आयोजनों पर लगाम:*

शादी जैसे बड़े आयोजनों के लिए 2 लाख से अधिक कैश भुगतान करना अब अवैध है। क्या सरकार यह मानती है कि हर व्यक्ति डिजिटल भुगतान या बैंकिंग माध्यमों से ही लेन-देन करेगा? ग्रामीण भारत में, जहां कैश ही प्रमुख साधन है, लोग कैसे व्यवस्थाएं करेंगे?

3. 50,000 से अधिक बैंक जमा पर पैन अनिवार्य:*

यदि आप बैंक में 50,000 या इससे अधिक की राशि जमा करते हैं, तो आपको पैन नंबर देना होगा। यहां तक कि साल में 10 लाख से अधिक जमा होने पर आयकर विभाग को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। क्या हर आम नागरिक अब संदिग्ध की नजरों से देखा जाएगा?

4. *संपत्ति लेन-देन में कैश पर रोक:*

2 लाख से अधिक के संपत्ति लेन-देन के लिए कैश का उपयोग अब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। क्या हर किसी के पास बैंकिंग माध्यम तक आसान पहुंच है?

कैश लेन-देन: अपराध या मजबूरी?*

इन नियमों का उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना और वित्तीय लेन-देन को पारदर्शी बनाना बताया जा रहा है। लेकिन क्या सरकार ने यह सोचा है कि ये नियम आम आदमी की दैनिक जिंदगी को कितना कठिन बना सकते हैं?

- छोटे व्यापारी, जिनके लिए कैश लेन-देन ही आजीविका का साधन है, क्या वे इन नियमों का पालन कर पाएंगे?
- ग्रामीण इलाकों में, जहां बैंकिंग सुविधाएं सीमित हैं, लोग कैश का विकल्प कैसे ढूंढेंगे?

जनता के लिए सवाल, सरकार के लिए चुनौती*

सरकार ने इन नियमों को लागू करके यह संदेश दिया है कि कैश लेन-देन करना अब एक बड़ा जोखिम है। लेकिन क्या यह नियम हर नागरिक के लिए व्यावहारिक हैं?

- जब तकनीकी बाधाएं और बैंकिंग सुविधाओं की कमी आज भी एक सच्चाई हैं, तो आम जनता को इन नियमों के तहत कैसे लाया जाएगा?
- क्या सरकार आम जनता के जीवन को आसान बनाने के बजाय उसे और जटिल बना रही है?

आखिर जनता कब तक सहेगी?*

सरकार से सवाल है:

- क्या आप जनता के लिए ऐसी नीतियां बनाएंगे, जो व्यवहारिक हों और उनकी वास्तविक समस्याओं का समाधान करें?
- क्या आम आदमी को अपने ही पैसे के इस्तेमाल के लिए हर बार सफाई देनी होगी?
- डिजिटल और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना अच्छी बात है, लेकिन क्या इसे लागू करने से पहले आप लोगों की तैयारियों और सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं?

अगर सरकार जनता की आवाज नहीं सुनेगी, तो कब सुनेगी? या फिर आम आदमी को इन नियमों के बोझ तले दबने के लिए छोड़ दिया गया है?

दिल्ली-एनसीआर में बीएस III और बीएस IV वाहनों पर प्रतिबंध को लेकर परिवहन समुदाय में भारी आक्रोश

परिवहन विशेष न्यूज

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के नेतृत्व में परिवहन समुदाय ने दिल्ली सरकार और सीएक्यूएम के इस निर्णय को अल्पदृष्टि वाला और विनाशकारी बताया। दिल्ली में ट्रक चालकों और छोटे ऑपरेटरों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। आज इस मुद्दे पर होटल सिद्धार्थ, दिल्ली में परिवहन समुदाय की एक अहम बैठक हुई।

अब जानते हैं इस खबर की पूरी कहानी।

मुख्य बिंदु:

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, जो पिछले 86 वर्षों से 95 लाख ट्रक चालकों और 50 लाख बस, टूरिस्ट टैक्सी और मैक्सी कैब संचालकों का प्रतिनिधित्व करती है, ने दिल्ली-एनसीआर में बीएस III और बीएस IV वाहनों के प्रतिबंध को ₹अप्रभावी और अनुचित" करार दिया है।

इस प्रतिबंध का उद्देश्य प्रदूषण को नियंत्रित करना बताया गया है। लेकिन परिवहन समुदाय का कहना है कि यह निर्णय सतही है और प्रदूषण स्तर को सार्थक रूप से कम करने में असफल रहा है। इसके बजाय, यह प्रतिबंध ट्रक चालकों और उनके परिवारों पर आर्थिक संकट और अमानवीय कठिनाइयां थोप रहा है।

बैठक का आयोजन और आंकड़े:

आज की बैठक में दिल्ली-एनसीआर के 11 से अधिक परिवहन संघों के नेताओं ने हिस्सा लिया।

बैठक में बताया गया कि:

- बीएस III और बीएस IV वाहनों के प्रतिबंध से अब तक *₹9500 करोड़ से अधिक का नुकसान* हो चुका है।
- लगभग *1,15,945 हल्के और भारी ट्रक* दिल्ली में प्रवेश और निकास करते हैं।
- हर वाहन पर प्रति दिन ₹4000 का औसत नुकसान हो रहा है।
- बीते 20 दिनों में यह कुल वित्तीय नुकसान लगभग ₹9275 करोड़ तक पहुंच चुका है।

प्रमुख चिंताएं और मुद्दे:*

1. प्रदूषण नियंत्रण के आंकड़े और प्रभावशीलता:*

आईआईटी कानपुर के 2015 के अध्ययन के अनुसार, दिल्ली में प्रदूषण का 20% योगदान वाहनों से होता है।

- इसमें निजी कारें और दोपहिया वाहन भी शामिल हैं।
- उस समय ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे चालू नहीं थे।
- अब इन एक्सप्रेसवे के चालू होने से गैर-जरूरी ट्रकों का दिल्ली में प्रवेश काफी हद तक कम हो चुका है।

2. अन्य प्रदूषण स्रोत:*

- पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फसल जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है।
- औद्योगिक प्रदूषण और सड़क की धूल अनियंत्रित हैं।
- बीएस IV और बीएस VI वाहन एडब्ल्यू का उपयोग करते हैं, जो कम प्रदूषण करते हैं।

3. आर्थिक संकट:

- हजारों ट्रक, जो जरूरी और गैर-जरूरी सामान लेकर आ रहे हैं, सीमा पर फंसे हुए हैं।
- फल, सब्जियां, दूध और दवाइयों जैसी जरूरी वस्तुएं सड़ रही हैं।
- ई-वे बिल समाप्त होने और भारी जुर्माने से ऑपरेटरों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

4. मानवीय संकट:

- फंसे हुए ट्रक चालकों और उनके कर्मचारियों को भोजन, पानी और बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
- उनकी स्थिति असुरक्षित और अमानवीय हो गई है।
- छोटे ऑपरेटर दिवालिया होने की कगार पर हैं।

5. अनुचित लक्षितकरण:*

- बीएस III और बीएस IV वाहन सख्त उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं।
- फिर भी इन पर प्रतिबंध लगाना अनुचित है।
- मुंबई और अन्य शहरों में बीएस III और बीएस IV वाहनों को प्रवेश की अनुमति है, फिर वहां प्रदूषण की समस्या उतनी गंभीर नहीं है।

-

परिवहन समुदाय की मांगें:

बैठक में परिवहन समुदाय ने सरकार और सुप्रीम कोर्ट से ये मांगें रखीं:

1. वैध पीयूसीसी वाले बीएस III और बीएस IV वाहनों पर प्रतिबंध तुरंत हटाया जाए।
2. सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाए।
3. प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यावहारिक कदम उठाए जाएं।
4. ट्रक ऑपरेटरों और परिवहन समुदाय को हुए वित्तीय नुकसान का मुआवजा दिया जाए।
5. सरकार कृत्रिम वर्षा (आर्टिफिशियल रेन) जैसे उपाय अपनाए।
6. ग्रीन कवर बढ़ाने और अन्य स्थायी उपायों पर ध्यान दिया जाए।

आगे की कार्रवाई:

परिवहन समुदाय ने निर्णय लिया है कि 5 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया जाएगा। अगर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो दिल्ली-एनसीआर में सभी परिवहन संचालन निलंबित करने पर विचार किया जाएगा।

सरकार से अपील है कि वह इस गंभीर आर्थिक और मानवीय संकट को समझे। प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस और व्यावहारिक समाधान निकाले।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

डीटीसी कर्मियों का दिल्ली सरकार को अल्टीमेटम, 9 दिसंबर से करेंगे चक्का जाम, 41 लाख लोगों को हो सकती है परेशानी

परिवहन विशेष न्यूज

नईदिल्ली: दिल्ली परिवहन निगम के करीब 27 हजार संविदा कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मार्शलों की राह पर चल पड़े हैं. दरअसल, डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों का समाधान न होने पर डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने 9 दिसंबर से सभी डिपो में बसों का चक्का जाम किए जाने की घोषणा की है. बीते महीने दिल्ली में डीटीसी कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, उस दौरान बसों का संचालन काफी प्रभावित हुआ था. तब DTC बसों से सफर करने वाले लाखों यात्री परेशान हुए थे.

डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के प्रेसिडेंट ललित चौधरी का कहना है कि मुख्यमंत्री आतिशी, डीटीसी और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कर्मचारियों के साथ बैठक कर उनकी कई मांगों को मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उसे पूरा नहीं किया गया है. ऐसे में अब विभाग के अधिकारियों को मांगें पूरी करने के लिए आज यानी पांच दिसंबर तक का ही समय दिया गया है. इस अवधि में अगर मांगें नहीं पूरी की गई तो 9 दिसंबर से सभी डिपो में बसों का चक्का जाम किया जाएगा.

डीटीसी कर्मचारियों को नोटिस जारी: दूसरी तरफ, डीटीसी बसों का संचालन रुकने के डर से विभाग की ओर से ये नोटिस जारी किया है. जिसमें कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी कर्मचारी 5 से 9 दिसंबर तक छुट्टी पर रहता है तो माना जाएगा कि वह डीटीसी के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल है और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है. दिल्ली में एक बार फिर डीटीसी बसों का संचालन रुकने के डर से विभाग की ओर से ये नोटिस जारी किया गया है.

DTC कर्मचारियों को नोटिस, 5 से 9 दिसंबर के बीच छुट्टी ली तो खैर नहीं, जानिए क्यों हो रही ये सख्ती ?

DTC के स्थायी व कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर भी चलाएंगे इलेक्ट्रिक बसें, दिलाई जाएगी ट्रेनिंग

DELHI: DTC कर्मचारियों को वादा पूरा होने का इंतजार, सीएम आतिशी ने दिया था आश्वासन

इन मांगों को लेकर DTC कर्मचारी है अडिगः यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी के मुताबिक, 10-15 सालों से संविदा पर कर्मचारी काम कर रहे हैं. इन कर्मचारी द्वारा नीचे दिए विभिन्न मांगों को लेकर बीते दो महीनों में दो बार धरना दिया जा चुका है. बीते नवंबर में दिए गए धरने के दौरान सीएम आतिशी और डीटीसी के अधिकारियों ने मांगों पर विचार के लिए 15 दिन का समय मांगा था. अब यह अवधि पांच दिसंबर को पूरी हो रही है.

तनख्वाह का भुगतानःकर्मचारियों की तनख्वाहों में देरी हो रही है, जिसके कारण वे आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं. जल्द से जल्द तनख्वाह का भुगतान किया जाए.

कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का स्थायीकरण: सभी अनुबंधित कर्मचारियों को स्थायी किया जाए और जब तक स्थायीकरण प्रक्रिया पूरी न हो, समान काम का समान वेतन लागू किया जाए.

अनुकंपा आश्रित और संवाहकों का नियमितीकरण: लंबे समय से अनुबंध पर काम कर रहे संवाहकों को नियमित किया जाए और उनकी सेवाओं को स्थायी किया जाए.

टीए, सीएल, और सरकारी अवकाश की सुविधा :डीटीसी अनुबंध कर्मचारियों को यात्रा भत्ता (टीए) और 15 दिन की चतुर्थ श्रेणी अवकाश (सीएल) दिया जाए, जैसा कि डिम्ट्स कंपनी में दिया जाता है. साथ ही, कर्मचारियों को सरकारी अवकाश का भुगतान भी किया जाए.

ड्यूटी और वेतन में सुधार: कर्मचारियों की ड्यूटी 8-30 घंटे निर्धारित की जाए, और ओवरटाइम की स्थिति में उन्हें दोगुना वेतन दिया जाए. इसके अलावा, डिपो मैनेजरों को कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हर महीने एक दिन निर्धारित किया जाए.

कंपनी के एग्रीमेंट का पुनः मूल्यांकन: प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों से जो एग्रीमेंट साइन कराया जाता है, उसे गैर संवैधानिक और शोषणपूर्ण बताया गया है, और इसे तत्काल रद्द करने की मांग की गई है.

इलेक्ट्रिक बसों की दुर्घटनाओं पर प्रतिक्रिया: इलेक्ट्रिक बसों से बढ़ती दुर्घटनाओं के मद्देनजर, यूनियन ने प्रस्तावित किया है कि डीटीसी के अनुभवी ड्राइवरों को ही इन बसों का संचालन सौंपा जाए, ताकि कर्मचारी बेरोजगार न हों.

यूनियन ने डीटीसी विभाग में 60% स्थाई और 40% अनुबंध कर्मचारी रखने का भी आग्रह किया है, जैसा कि कंपनी एक्ट के तहत नियम है, लेकिन वर्तमान में 100% संवाहक कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं.

प्रदर्शन से लाखों लोग होंगे परेशान: अगर आज डीटीसी के संविदा कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं की गई, तो ये कर्मचारी 9 दिसंबर से सभी डिपो में एक साथ बसों का चक्का जाम करेंगे. इससे दिल्ली में लाखों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. दिल्ली में रोजाना बसों में 41 लाख लोग सफर करते हैं. कर्मचारियों के प्रदर्शन से बसों का संचालन प्रभावित होगा, जिसका असर सीधा यात्रियों पर पड़ेगा. हालांकि डीटीसी के अधिकारी भी चाहते हैं कि यह आंदोलन न हो और जल्द से जल्द संविदा कर्मचारियों की दो-तीन मांगों को पूरा कर लिया जाए.

17 नवंबर को कर्मचारियों ने की थी हड़ताल: बता दें, इससे पहले डीटीसी के कर्मचारियों ने 17 नवंबर को हड़ताल की थी. तब डीटीसी के बसों में सफर करने वाले लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसके चलते कई लोग मेट्रो से सफर किए, तो कई अन्य साधनों के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंच थे. इसके बावजूद लोग जद्दोजहद करते हुए दिखाई दिए थे. उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में लंबा इंतजार करना पड़ा था।

नेपाल का जनकपुर जहां धूमधाम से मनता है राम जानकी विवाहोत्सव

(कुमार कृष्णन-विभूति फीचर्स)

जनकपुर नेपाल ही नहीं अपितु दुनिया भर के लोगों के लिये अत्यंत पावन तीर्थ है ।भगवान राम और माता जानकी का परिणय जनकपुर में हुआ था ।केवल नेपालवासी ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लाखों राम भक्त विवाह पंचमी के दिन जनकपुर पहुंच कर राम जानकी विवाहोत्सव में सम्मिलित होते हैं।

नेपाल आने वाले पर्यटकों के लिए जनकपुर एक बेहद खास जगह है। जनकपुर नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है जो पर्यटकों के साथ ही तीर्थयात्रियों के लिए भी एक पसंदीदा जगह है। यह शहर अपने सुखद मौसम, भव्य उत्सव, मंदिरों की आकर्षक वास्तुकला से सभी को आकर्षित करता है। इस शहर में कई तालाब है जो यात्रियों को आकर्षित करते हैं। राजा जनक के नाम पर इस नगर का नाम जनकपुर रखा गया था।

जनकपुर नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहां स्थित जानकी मंदिर की कलाकृति बेहद अद्भुत है।

नेपाल स्थित जानकी मंदिर एक ऐतिहासिक स्थल होने के साथ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। मंदिर का निर्माण हिन्दू-राजपूत वास्तुकला पर आधारित है। यह नेपाल में सबसे महत्वपूर्ण राजपूत स्थापत्यशैली का उदाहरण है। जानकी मंदिर में तीर्थ यात्री न सिर्फ़ भारत से बल्कि विदेशों से भी आते हैं। यहां यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से भी तीर्थ यात्री आते हैं।

ब्रह्मर्षि राजा जनक अपने युग के प्रख्यात नरेश थे।

'शतपथ ब्राहमण', 'तैतिरीय ब्राहमण', 'वृहदारण्यक' उपनिषद् इत्यादि में उसकी चर्चा अनेक बार आयी है।'वृहद्विष्णुराण' के अनुसार तीर्थाटन की पूर्णाहुति वहीं । जाकर होती थी। वैसे तो यहां अनेक मंदिर, मंडप, कुंड इत्यादि हैं परन्तु प्रमुख जानकी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, विवाह मंडप एवं राम मंदिर हैं। उनमें प्रथम तीन तो एक ही विशाल प्रांगण में अवस्थित हैं।

त्रेता युग के बाद मिथिला राज्य के अंतिम नरेश के रूप में कराल जनक का उल्लेख चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में करता है ।सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र खंड में नेत्र चिकित्सा अध्याय में भी जनक का उल्लेख नेत्र चिकित्सा के सर्वोत्कृष्ट सर्जन के रूप में किया गया है । ये दो उल्लेख इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त हैं कि रामजी की कथा केवल धार्मिक साहित्य नहीं अपितु भारत वर्ष के प्राचीन इतिहास के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

माता सीता को समर्पित इस मंदिर को ऐतिहासिक स्थल भी माना जाता है। मिथिला जहां माता सीता का जन्म हुआ और उनके विवाह के बाद यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम चंद्र जी का ससुराल बना ।आज भी इस मंदिर में ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जो रामायणकाल का उल्लेख करते हैं।

जानकी मंदिर नेपाल के जनकपुर धाम में स्थित है। विख्यात माता सीता का यह मंदिर 4860 वर्गमीटर में फैला हुआ है।

किलेनुमा दीवारों से घिरे वहां के सर्वप्रमुख एवं विशाल जानकी मंदिर के निर्माण की कथा है कि विवाहोपरान्त जब सीता राम जनकपुर से प्रस्थान करने लगे तो दुःख से जनक मूर्च्छित हो गये। उन्होंने सीता राम के स्मरणार्थ विश्वकर्मा से मूर्तियां तैयार करने का अनुरोध किया। कालांतर में वे मूर्तियां भूमिसात्हो गयी।

किंवदन्तियों के अनुसार यहां जानकी मंदिर के समक्ष स्थित लक्ष्मण मंदिर का ही निर्माण सर्वप्रथम हुआ। कहा जाता है कि मिथिला में हति के पुत्र तथा कृति के पिता बहुलाश्व नामक जनकवंशीय अंतिम नरेश के समय भीषण अकाल पड़ा जिससे मुक्ति के लिए उन्होंने स्वयं उत्तराखंड में बारह वर्षों तक जब तपस्या की । तब उन्हें शेष नारायण भगवान ने एक उपाय बताते हुए कहा कि 'मैं प्रत्येक त्रेतायुग में श्रीराम के अनुज लक्ष्मण के रूप में जन्म ग्रहण करता हूं, इसलिए मेरा एक मंदिर बनवायें। कालक्रम में वह मंदिर जब विनष्ट प्रायः होने लगा तो जीर्णोद्धार भी कराया गया।

इस मंदिर के निर्माण में करीब 16 साल का समय लगा था यानि मंदिर का निर्माण 1895 ईस्वी में शुरु हुआ और 1911 में संपूर्ण हुआ था।

कहते हैं टीकमगढ़ राजवंश की भगवान राम में गहरी आस्था रही है। इन्होंने अयोध्या, ओरछा और जनकपुर में भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। इतिहासकार बताते हैं कि त्रेता युगकालीन जनकपुर का वेद पुराणों में जिक्र मिलता है। लेकिन इस जगह की पहचान होना काफी मुश्किल था। 16वीं सदी शताब्दी में ओरछा के शासक मधुकरशाह की महारानी गणेश कुंवर अयोध्या से रामलला को ओरछा ले आईं। इसके 200 साल बाद जनकपुर में जानकी मंदिर बनवाने का जिम्मा टीकमगढ़ राजपरिवार में अगली पीढ़ी की महारानी ने संभाल लिया। 1896 से टीकमगढ़ की महारानी सवाई महेन्द्र प्रताप सिंह बुंदेला की पत्नी वृषभानु कुमारी ने नेपाल के जनकपुर में मंदिर निर्माण शुरू करा दिया, जिसके नौलखा नाम से पहचाने जाने की कहानी भी कहानी कम रोचक नहीं है।

टीकमगढ़ महाराज महेन्द्र प्रताप सिंह और महारानी वृषभानु कुमारी के संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए महारानी वृषभानु कुमारी ने अयोध्या में 'कनक भवन मंदिर' का निर्माण करवाया था, लेकिन पुत्र प्राप्त न होने पर अपने गुरु की आज्ञा से 1896 में उन्होंने देवी सीता का मंदिर जनकपुर में बनवाने का संकल्प लिया। उन्होंने 1896 ई. में जानकी मंदिर का निर्माण करवाया और इसके एक वर्ष में ही उनको पुत्र की प्राप्ति हो गई।

भगवान राम की अर्धांगिनी देवी सीता के जनकपुरी में बन रहे मंदिर का निर्माण कराने के लिए टीकमगढ़ की महारानी वृषभानु कुमारी ने नौ लाख रुपए खर्च करने का संकल्प लिया था। इसके लिए पहले जनकपुर गांव को बसाया गया, क्योंकि वह वीरान क्षेत्र था ।फिर वहां मंदिर का निर्माण शुरू कराया ।नौ लाख खर्च करने के संकल्प पर इस मंदिर का नाम भी 'नौलखा' पड़ गया। विश्वजीत सिंह बुंदेला कहते हैं, इसका नाम ही नौलखा है लेकिन इसके निर्माण पर 18 लाख से भी अधिक की धनराशि खर्च हुई थी और इसका निर्माण भी कई साल चलता रहा। जानकी मंदिर के निर्माण काल में ही वृषभानु कुमारी का निधन हो गया । उनके निधन के बाद वृषभानु कुमारी की बहन नरेंद्र कुमारी ने मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाया। बाद में महाराज प्रताप

सिंह ने नरेंद्र कुमारी से विवाह कर लिया। जानकी मंदिर 1911 में पूरी तरह बनकर तैयार हो गया ।इसमें मूर्ति स्थापना पहले ही करके पूजा प्रारंभ कर दी गई थी ।जनकपुर में जानकी जी का भव्य मंदिर तो बनकर खड़ा हो गया था, लेकिन इतने विशाल मंदिर का प्रबंधन बनाए रखना आसान नहीं था। जब मंदिर के खर्च की बात सामने आई तो टीकमगढ़ महाराज ने नेपाल में मंदिर के नाम पर काफी जमीन दे दी और यही जमीन मंदिर की आमदनी का प्रमुख स्रोत बनी रही। यहां जंगल हुआ करता था, जहां शुरकिशोर दास तपस्या-साधना करने पहुंचे थे ।यहां रहने के दौरान उन्हें माता सीता की एक मूर्ति मिली थी, जो सोने की थी ।उन्होंने ही इसे वहां स्थापित किया था।

इतिहासकारों के मुताबिक 1657 ईस्वी में यहां पर माता सीता की सोने की मूर्ति मिली थी। भगवान राम ने यहीं पर माता सीता से विवाह के लिए स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष तोड़ा था। यहां मौजूद पत्थर के टुकड़े को धनुष का अवशेष कहा जाता है।

रामायणकाल के अनुसार माता सीता ने धरती मां के गर्भ से जन्म लिया था और वे निसंतान राजा जनक को खेत में हल चलाते समय मिली थी। कहा जाता है कि जनकपुर धाम में आज भी वह स्थान मौजूद है जहां पर राजा जनक को माता सीता प्राप्त हुई थी। सीता जयंती और विवाह पंचमी के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर आते हैं और विधि विधान से माता सीता की पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर में साल भर अखंड कीर्तन चलता रहता है। 24 घंटे सीता-राम नाम का जाप यहां लोग करते हैं। साल 1967 से लगातार यहां अखंड कीर्तन चल रहा है ।वर्तमान में राम तपेश्वर दास वैष्णव इस मंदिर के महंत हैं। वे जानकी मंदिर के 12वें महंत हैं। परंपरानुसार अगले महंत का चुनाव वर्तमान महंत करते रहे हैं। महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव तीसरे महंत हैं, जिनका चुनाव इस प्रक्रिया के तहत किया गया है। 10वें महंत से पहले मंदिर के प्रमुख का चुनाव अलग विधि से किया जाता था और धर्मज्ञानी को इस पद पर बिठाया जाता था।

राम-जानकी विवाह मार्गशीर्ष के शुक्लपक्ष की पंचमी तिथि के दिन हुआ था, इस दिन को श्रीराम पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। हर साल धूमधाम से राम-जानकी विवाहोत्सव मनाया जाता है। यहां नेपाल और भारत के अलावा अन्य देशों से भी भक्त दर्शन करने आते हैं। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से हर साल राम बारात जनकपुर के लिए रवाना होती है। विवाह पंचमी के दिन 'श्री सीताराम विवाह महोत्सव' कार्यक्रम को संपन्न कराने तिरुपति बालाजी से लगभग 40 वैदिक ब्राह्मणों की टीम सीधे जनकपुर पहुंचती है।

जानकी मंदिर के आसपास 115 सरोवर और कुंड हैं, जिसमें से गंगा सागर, परशुराम सागर एवं धनुष सागर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है।

जानकी मंदिर की बायीं ओर अवस्थित भव्य विवाह मंडप, सीताराम के मूल विवाह मंडप 'मणि मंडप' से करीब दो किलोमीटर पर हैं, जिसके निर्माण में महन्त नवलकिशोरदास जी की प्रेरणा है। वैसे उन्होंने 'मणि-मंडप' में 'विवाह मंडप' बनाने की तैयारी आरंभ कर दी थी किन्तु उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर महन्त रामशरणदासजी के प्रयास से नेपाल नरेश ने उस विवाह मंडप को बनवाया। उसमें सीताराम के माता पिता के साथ ही श्रीराम एवं सीता के क्रमशः सहचर चारूशीलाजी तथा चन्द्रकलाजी प्रसादाजी की विशाल और भव्य प्रतिभाएं हैं ।यहां अन्य देवी-देवताओं की भी प्रतिमाएं है। मंडप के चारों ओर चार छोटे-छोटे 'कोहबर' हैं जिनमें सीता-राम, माण्डवी-भरत, उर्मिला-लक्ष्मण एवं श्रुतिकीर्ति-शत्रुध्न की मूर्तियां हैं।

राम मंदिर यहां के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जिसे गोरखा जनरल अमर सिंह थापा ने 1700 साल पहले बनवाया था। यहां राम नवमी और दशहरे पर भारी संख्या में भक्तों का तांता लगा रहता है ।राम-मंदिर के विषय में जनश्रुति है कि अनेक दिनों तक सुरकिशोरदासजी ने जब एक गाय को वहां दूध बहाते देखा तो खुदाई करवायी जिससे श्रीराम की मूर्ति मिली। महंत ने वहां एक कुटिया बनाकर, उसका प्रभार एक संन्यासी को सौंपा, इसलिए अद्यपर्यन्त राम मंदिर के महन्त संन्यासी ही होते हैं जबकि वहां के अन्य मंदिरों के महंत वैरागी हैं।

दोला भीमसेन मंदिर मुख्य शहर जनकपुर से करीब 107 किमी दूर स्थित है और भीम को समर्पित करते हुए बनाया गया है। महाभारत के पांच पांडवों में एक भीम युधिष्ठिर से छोटे दूसरे नंबर के पांडव थे। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस पर छत नहीं है। यहां भीम के अलावा मां भगवती, और भगवान शिव की प्रतिमा भी स्थापित हैं।

जनकपुर में अनेक कुंड हैं यथा-रत्ना सागर ,अनुराग सरोवर, सीताकुंड इत्यादि। 'धनुखा' जनकपुर से 40 किमी दूर स्थित है, जिसे धनुष सागर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि जब भगवान राम ने शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो वह तीन टुकड़ों में टूट गया। इस धनुष का एक हिस्सा उड़कर स्वर्ग पहुंचा। दूसरा हिस्सा पाताल में जा गिरा, जिसके ठीक ऊपर विशाल धनुष सागर है और तीसरा हिस्सा यहां जनकपुर के पास आ गिरा। जिसे आज धनुषधाम मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि वहां प्रत्येक पच्चीस तीस वर्षो पर धनुष की एक विशाल आकृति बनती है जो आठ-दस दिनों तक दिखाई देती है ।मंदिर से कुछ दूर 'दूधमती' नदी के बारे में कहा जाता है कि भूमि से उत्पन्न शिशु सीता को दूध पिलाने के उद्देश्य से कामधेनु ने जो धारा बहायी, उसने उक्त नदी का रूप धारण कर लिया।

रत्नासागर मंदिर लुम्बिनी में स्थित है। यह मंदिर भगवान और सीता माता को समर्पित है। यह विशाल मंदिर चारों ओर से खूबसूरत बगीचे और एक पवित्र जलस्रोत रत्ना सागर से घिरा हुआ है। इसलिए इस मंदिर का नाम रत्ना सागर मंदिर रखा गया है। लुंबिनी गौतम बुद्ध की जन्म स्थली के रुप में विख्यात है इसलिए यह स्थान बौद्ध धर्म का भी प्रमुख स्थल है।

गंगासागर विशाल और पवित्र झील है। यह जनकमहल के करीब स्थित है। धनुष सागर और रत्ना सागर के अलावा यह पवित्र जलस्रोत मानी जाती है। इसके निकट ही 70 साल पुराना पुस्तकालय स्थित है। यहां दूर-दूर से लोग आते हैं।

सीताराम के संबंध के कारण भारत एवं नेपाल के श्रद्धालुगण एक-दूसरे को अलग अलग देशों के नहीं समझते। जनकपुर तो दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंध का केन्द्रबिन्दु या नाभिस्वरूप है। रामायण सर्किट योजना के पहले चरण में अयोध्या से जनकपुर के बीच अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा शुरू की गई है जो गोपालगंज के रास्ते एनएच 28 से भारत और नेपाल की पौराणिक रिश्ते को प्रगाढ़ कर रही है। अब माता सीता के मायके और ससुराल की दूरी कम करने की दिशा में राज्य सरकार बैकुंठपुर के सत्तर घाट में गंडक नदी पर 300 करोड़ की लागत से महासेतु का निर्माण करा रही है। पुल निर्माण का काम अंतिम चरण में है ।शीघ्र ही इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। केन्द्र सरकार ने दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय और पौराणिक रिश्ते को और मजबूत करने के लिए राम-जानकी मार्ग के विस्तार के लिए स्वीकृति देते हुए कार्य की शुरूआत कर दी है। इसके तहत जिले में 11 किमी लंबी नई फोरलेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सर्वे और जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया गया है। सीवान, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण को रामायण सर्किट से जोड़ने वाली 83.24 किमी लंबी सड़क के चौड़ीकरण पर 1285 करोड़ की राशि खर्च हो रही है ।काठमांडू से जनकपुर विभिन्न मार्गों से आसानी से पहुँचा जा सकता है। काठमांडू से बस से 400 किलोमीटर का रास्ता है ।जिसमें 7-8 घंटे का समय लगता है ।इसके अलावा नेपाल के विभिन्न शहरों से जनकपुर के लिए गाडियां जाती रहती हैं।

भारत के अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए जयनगर से होकर जाना सुविधाजनक होता है। यह बिहार में हैं, सीमा से करीब है। यहां से बस सीधे जनकपुर जाती हैं। दूसरा रास्ता सीतामढ़ी शहर से भिट्ठामोड़ होते हुए जलेश्वर 19 किलोमीटर वहां से जनकपुर धाम 30 किलोमीटर है ।नेपाल सरकार ने नये रेल मार्ग का निर्माण कर जनकपुर धाम से जयनगर के लिए रेलवे सेवा प्रदान की है। बिहार राज्य का जयनगर भारत के विभिन्न राज्यों के रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट है ।आप जयनगर आकर रेल द्वारा सीधे जनकपुर धाम पहुंच सकते हैं।

शी-बॉक्स पोर्टल- महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुरक्षित व संरक्षित बनाने व महिला कार्यबल विज़न 2047 में मील का पत्थर साबित होगा

नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी को सुरक्षित पंख लगाने शी बॉक्स पोर्टल मज़बूत आधार
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों को शी- बॉक्स पोर्टल से त्वरित एक्शन दिखेगा- एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर भारत के विज़न 2047 की पूरी दुनिया में गूंज हो रही है जो हर क्षेत्र में विकसित भारत के लिए बनाए गए रोड मैप का एक संयुक्त पत्रक है, जिसका एक महत्वपूर्ण भाग महिलाओं के नेतृत्व को आगे बढ़ना भी है, जिसके लिए यह जरूरी है कि उनके लिए राजनीतिक सामाजिक कार्यपालिका सहित सभी क्षेत्रों में अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक सुरक्षित संरक्षित माहौल बनाया जाए, ताकि उनके टैलेंट को पंख लगा सके परंतु ऐसा देखा गया है कि इन क्षेत्रों में महिलाओं का यौन उत्पीड़न होने की शिकायतें सामने आई तो सरकार ने इसको रेखांकित कर कार्य स्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (शिकायत निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 बनाया परंतु उसके क्रियान्वयन में देरी व लीकेजेस को रेखांकित कर 29 अगस्त 2024 को एक कार्यक्रम में शी-बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसमें महिलाओं की शिकायतें दर्ज कर निगरानी करने, व त्वरित कार्रवाई करने का एकीकृत प्लेटफार्म है, जिसपर सभी संबंधितों की नजर होगी, इसलिए पारदर्शिता से कार्रवाई शीघ्र होगी जो 90 दिन निर्धारित हैं। इस विषय पर आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत में शुरू संसद के शीत सत्र 2024 में दिनांक 4 दिसंबर 2024 को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में महिला बाल विकास कल्याण राज्यमंत्री ने उसके उत्तर में सटीक बातें कही, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, शी-बॉक्स पोर्टल महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुरक्षित व संरक्षित बनाने व महिला कार्यबल मिशन 2047 में मील का पत्थर साबित होगा।

साथियों बात अगर हम शी-बॉक्स पोर्टल को जानने की करें तो, कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से ये महत्वपूर्ण कदम है ।यह पोर्टल देश में आंतरिक समितियों और स्थानीय समितियों से संबंधित सूचनाओं के लिए एक स्टोरेज के रूप में काम करेगा, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर होंगे ।यह पोर्टल महिलाओं को शिकायत दर्ज करने, उनकी स्थिति पर निगरानी रखने तथा यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि उनकी शिकायतों का समय पर निपटारा हो, इसके लिए शिकायतों की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि महिला को न्याय मिल सके,. केंद्रीय मंत्री ने कहा, इस पहल से कार्यस्थल से संबंधित यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करने के लिए पहले से अधिक कुशल और सुरक्षित मंच उपलब्ध कराया जा सकेगा, यह कदम देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित और अधिक समावेशी कामकाज का वातावरण बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है ।कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ कुकृत्य के बाद ही देश में आक्रोश का माहौल है, लोग इस घटना के बाद वर्क स्पेस पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे थे, ऐसे में सरकार वर्क स्पेस पर महिलाओं के काम करने और उनकी सुरक्षा को लेकर कई कदम उठा रही है।

साथियों बात अगर हम शी-बॉक्स पोर्टल की विधि को जानने की करें तो, (1) विजिट वेबसाइट- सबसे पहले नोटिफिकेशन में दी गई वेबसाइट पर जाएं।(2) रजिस्टर कंप्लेंट- होम पेज पर रेड कलर में रजिस्टर योर कंप्लेंट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर टैप करने के बाद आप कंप्लेंट रजिस्टर्ड पेज पर पहुंच जाएंगे।(3) कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पेज पर प्रक्रिया शुरू करने के लिए रजिस्टर कंप्लेंट करें पर टैप करें।(4) यहां दो ऑप्शन होंगे- सेंट्रल गवर्मेंट ऑफिस और स्टेट गवर्मेंट ऑफिस, आपको सेंट्रल गवर्मेंट ऑफिस पर टैप करना है। (5) पर्सनल डिटेल- अब आपके सामने पर्सनल डिटेल फिल करने का ऑप्शन आएगा। इसमें नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल और इम्प्लॉयमेंट स्टेट्स, इंसीडेंट डिटेल और एविडेंस जैसी चीजें शामिल हैं। (6) रिव्यू एंड सबमिट- एक बार ये सारी चीजें फिल करने के बाद रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा। जिस पर टैप कर दें ।अब शी-बॉक्स पोर्टल के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा होगी। सरकारी और निजी संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न सहित अन्य तरह की ज्यादती होने पर इसकी ऑनलाइन शिकायत शी-बॉक्स पोर्टल पर जाकर दर्ज करा सकती हैं। संबंधित विभाग इस पर त्वरित पहल करते हुए संबंधित संस्थान या व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई करेगा। जिला स्तरपर इसका नोडल पदाधिकारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को बनाया गया है, जो स्थानीय स्तरपर शिकायतों का निवारण एवं आवेदन प्राप्त कर उचित कार्रवाई करेंगे। कोई भी महिला बाल विकास मंत्रालय के वेब पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद उस शिकायत को सीधे संबंधित नियोक्ता के आईसीसी/एलसीसी को भेज दिया जाएगा। इस पोर्टल के जरिए न केवल मंत्रालय, बल्कि शिकायतकर्ता भी जांच की प्रगति की निगरानी कर सकेंगी। इस पोर्टल के बारे में महिलाओं को अवगत कराने के लिए जिला प्रशासन इसका प्रचार-प्रसार करेगा।

साथियों बात अगर हम पोर्टल के उद्देश्यों को जानने की करें तो, भारत अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 की ओर बढ़ रहा है, सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर महत्वपूर्ण जोर दिया है। समावेशी आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए सरकार ने एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है जो महिलाओं को कार्यबल में सफल होने में सक्षम बनाता है। इस प्रयास की आधारशिला है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, जिसका उद्देश्य महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाना और उनकी शिकायतों का समाधान करना है। हाल ही में लॉन्च किया गया शी-बॉक्स पोर्टल इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुनिश्चित करता है कि शिकायतें न केवल दर्ज की जाएं बल्कि सक्रिय रूप से उनकी निगरानी भी की जाए, जिससे कार्यस्थल पर उत्पीड़न से निपटने के लिए एक मजबूत ढांचा उपलब्ध हो।

साथियों बात अगर हम 4 दिसंबर 2024 को लोकसभा में शी-बॉक्स पोर्टल संबंधी प्रश्न के लिखित उत्तर की करें तो, शी- बॉक्स पोर्टल मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उदेश्य देश भर में विभिन्न कार्यस्थलों पर गठित आंतरिक समितियों (आईसी) और स्थानीयसमितियों (एलसी) से संबंधित सूचनाओं का सार्वजनिक रूप से उपलब्ध केंद्रीकृत संग्रह उपलब्ध कराना है, चाहे वे सरकारी होंया निजी क्षेत्र के और साथ ही एक संपूर्ण एकीकृत शिकायत निगरानी प्रणाली भीइसमें प्रत्येक कार्यस्थल के लिए एक नोडल अधिकारी को नामित करने का प्रावधान है, जिसे शिकायतों की वास्तविक समय निगरानी के लिए नियमिआधार पर डेटा/जानकारी का अद्यतन सुनिश्चित करना होता है शी- बॉक्स पोर्टल पर दर्जकी गई कोई भी शिकायत सीधे संबंधित कार्यस्थल के आईसी या जिले के एलसी के पास पहुंचती है, जैसा भी मामला हो पोर्टल कोइस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह गोपनीयता बनाए रखने के लिए शिकायतकर्ता के विवरण को छुपाता है। आईसी एलसी के अध्यक्ष के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति दर्ज की गईशिकायत का विवरण या प्रकृति नहीं देख सकता हैके प्रावधानों के अनुसार किया गया हैअधिनियम के तहत जांच के लिए 90 दिन का समय निर्धारित है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे किशी-बॉक्स पोर्टल- महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुरक्षित व संरक्षित बनाने व महिला कार्यबल विज़न 2047 में मील का पत्थर साबित होगा ।नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी को सुरक्षित पंख लगाने शी बॉक्स पोर्टल सशक्त मज़बूत आधारकार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों को शी-बॉक्स पोर्टल से त्वरित एक्शन दिखेगा।

पेट में गैस की समस्या से छूटकारा पाने के आसान से घरेलू उपाय

1. नीबू के रस में 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर सुबह के वक्त खाली पेट पिएं।
2. काली मिर्च का सेवन करने पर पेट में हाजमे की समस्या दूर हो जाती है।
3. आप दूध में काली मिर्च मिलाकर भी पी सकते हैं।
4. छाछ में काला नमक और अजवाइन मिलाकर पीने से भी गैस की समस्या में काफी लाभ मिलता है।
5. दालचीनी को पानी मे उबालकर, ठंडा कर लें और सुबह खाली पेट पिएं। इसमें शहद मिलाकर पिया जा सकता है।
6. लहसुन भी गैस की समस्या से निजात दिलाता है। लहसुन को जीरा, खड़ा धनिया के साथ उबालकर इसका काढ़ा पीने से काफी फादा मिलता है। इसे दिन में 2 बार पी सकते हैं।
7. दिनभर में दो से तीन बार इलायची का सेवन पाचन क्रिया में सहायक होता है और गैस की समस्या नहीं होने देता।

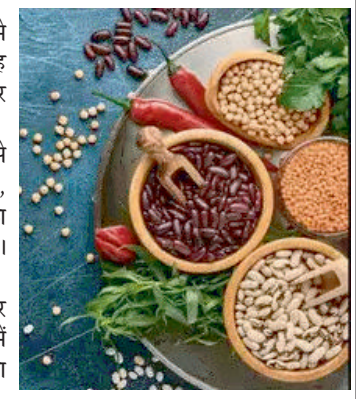

8. रोज अदरक का टुकड़ा चबाने से भी पेट की गैस में लाभ होता है।
9. पुदीने की पत्तियों को उबाल कर पीने से गैस से निजात मिलती है।
10. रोजाना नारियल पानी सेवन करना गैस का फायदेमंद उपचार है।

दिल्ली में तंबाकू बेचने वाले हो जाएं सावधान, उपराज्यपाल के आदेश के बाद 74 दुकानदारों पर एक्शन

दिल्ली में तंबाकू बचने वाले दुकानदारों पर अब एक्शन हो रहा है। यह कार्रवाई उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश के बाद हो रहा है। जिसमें उन्होंने नशा मुक्त दिल्ली के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस एक माह के पायलट प्रोजेक्ट के तहत क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई की है। इन दुकानदारों पर भारी जुर्माना लगाया गया है।

नई दिल्ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर नशा मुक्त दिल्ली के लिए शुरू किए गए एक माह के पायलट प्रोजेक्ट के तहत क्राइम ब्रांच ने जिला पुलिस के साथ मिलकर कई स्कूलों के आसपास औचक निरीक्षण किया।

इस दौरान तंबाकू उत्पाद बेचने वाले 74 दुकानदारों के खिलाफ सरकारी आदेश का पालन न करने के आरोप में उनपर भारी जुर्माना लगा कार्रवाई की गई।

राज निवास में उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक

डीसीपी क्राइम ब्रांच भीष्म सिंह के मुताबिक नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) की 9वीं राज्य स्तरीय समिति की एक समीक्षा बैठक 26 नवंबर को राज निवास में उपराज्यपाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

बैठक में उपराज्यपाल ने तीन साल के भीतर ₹नशा मुक्त दिल्ली₹ के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए ठोस प्रयासों के महत्व पर जोर दिया था और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक महीने का व्यापक अभियान शुरू करने का निर्देश दिया था।

तंबाकू मुक्त वातावरण को बढ़ाने के लिए हो रही कानूनी कार्रवाई

जिसके तहत एक दिसंबर से दिल्ली में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ अभियान की शुरूआत की गई है। क्राइम ब्रांच के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक दिसंबर से मध्य, नई दिल्ली, शाहदरा, पश्चिम, दक्षिण, उत्तरी और दक्षिण-पूर्व जिले में स्कूलों के आसपास सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचने वाले 74 दुकानदारों की पहचान कर उन्हें दंडित किया गया।

साथ ही चार शेल्टर होम की जांच की गई। छात्रों की सुरक्षा और स्कूलों के आसपास स्वस्थ, तंबाकू मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने के लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

यह भी पढ़ें: 'अमित शाह जी ये क्या हो रहा है, कुछ तो कीजिए...'; अरविंद केजरीवाल ने गृहमंत्री से पूछे ये सवाल

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) छात्रों की भलाई और सीओटीपीए नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। एक महीने तक चलने वाले इस पायलट प्रोजेक्ट का उद्देश्य युवाओं और बच्चों को नशीली दवाओं के खतरे से बचाना है।

GRAP-4 और GRAP-3 के प्रतिबंध हटाए जाएं-SC

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में लागू GRAP-4 और GRAP-3 के प्रतिबंधों को हटाने के लिए कहा है। हालांकि GRAP-2 और GRAP-1 के प्रतिबंध अभी भी राजधानी में लागू रहेंगे। यानि अब दिल्ली में कई चीजों पर पाबंदियां हटेंगी। जिससे राजधानी के साथ-साथ ही NCR के लोगों को काफी राहत मिल जाएगी।

स्पीकर राम निवास गोयल को अरविन्द केजरीवाल की हार का पूर्व में आभास हो गया है, 2025 चुनाव में आम आदमी पार्टी जहाज डूबने जा रहा है: देवेन्द्र यादव

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल का दोबारा चुनाव न लड़ने का निर्णय सीधा अरविन्द केजरीवाल नेतृत्व के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी की खिसकती जमीन के चलते आम आदमी पार्टी के मंत्री और वरिष्ठ नेता या तो अन्य राजनीतिक दलों में शामिल हो रहे थे या आसन्न हार को देखते हुए राजनीति छोड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 60 से अधिक विधानसभाओं का सफर पूरा कर चुकी दिल्ली न्याय यात्रा से घबराई आम आदमी पार्टी को 2025 विधानसभा चुनाव में हार सुनिश्चित दिख रही है।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना के अध्यक्ष को निर्देश देने के बावजूद लंबित 12 सीएजी (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) रिपोर्टों को सदन के पटल पर रखने से इनकार करने के बाद अध्यक्ष के रूप में राम निवास गोयल की स्थिति में संकट में आई जिससे उन्होंने आत्म सम्मान का अपमान महसूस किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में अरविन्द केजरीवाल की तानाशाही के आगे किसी का वजूद नही है।

देवेन्द्र यादव ने कहा कि केजरीवाल सारे नियम-कायदों की धज्जियां उड़ाकर तानाशाही तरीके से काम करते हैं, जो करदाताओं के पैसे की खुली लूट करते हैं। उन्होंने कहा कि जनता में केजरीवाल के

खिलाफ माहौल और आम आदमी पार्टी में व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन और गरीबों की अनदेखी के कारण माहौल विपरित परिस्थियों में पहुँच गया है और राम निवास गोयल सहित इनके नेता या तो चुनाव लड़ना नही चाहते या अपनी सीट बदलकर दूसरी विधानसभाओं का रुख कर रहे है। 2025 चुनावों में केजरीवाल अपनी सीट बदलने वाले है। क्योंकि जनता के बीच उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

धार्मिक भेदभाव देश की प्रगति व देशवासियों के उत्थान में बाधक है : मौ0 ताहिर सिद्दीकी

सुषमा रानी

नई दिल्ली। सर्वसमाज राष्ट्रीय महासंघ की एक अहम बैठक दरियागंज स्थित शबनम विला में सम्पन्न हुई। सर्व समाज राष्ट्रीय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौहम्मद ताहिर सिद्दीकी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जावेद सिद्दीकी, चांद खां अब्बासी, डॉ0 मुश्ताक अंसारी, नियाज़ मंसूरी, राहत खान, खुर्शीद आलम, जाहिद हुसैन, असरार कुरैशी, जमील मलिक, नसीम अख्तर, मौहम्मद सलीम व मौहम्मद सुबहान आदि समाज के जिम्मेदार लोगों ने शिरकत की। इस बैठक में देश में बढ़ती नफ़रत को खत्म करके आपसी सौहार्द को कैसे कायम किया जाए इस विषय पर गहन चर्चा की गई। बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए और देश की तरक्की, जनमानस के उत्थान व भाईचारा कायम करने पर बल दिया ।

मौ0 ताहिर सिद्दीकी ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि वर्तमान परिवेश में धार्मिक भेदभाव अधिक देखने को मिल रहा है, जिस कारण आपसी सौहार्द को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा यह भेदभाव देश की प्रगति और देशवासियों के उत्थान में बाधक है। इसलिए हम सबको देश की एकता अखंडता के लिए प्रयास करने होंगे। जावेद सिद्दीकी ने कहा कि भाईचारे में बढ़ौत्तरी के लिए तरबियत और अखलाक में सुधार करना होगा। डॉ0 मुश्ताक अंसारी ने कहा कि देश में फैल रही नफ़रत में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार के मुखिया की पहल कारगर साबित हो सकती है, इसलिए हमें प्रयास करना होगा इस सामाजिक समस्या से मुखिया जी को अवगत कराया जाए। चांद खां अब्बासी ने कहा कि देश में सुधार शीर्ष नेतृत्व के प्रयास से ही आएगा। नियाज़ मंसूरी ने कहा कि समुदाय के उत्थान के लिए शिक्षा पर विशेष बल देना होगा और राजनीति के मोह को त्यागकर सामाजिक सेवाओं को बढ़ाना होगा। जाहिद हुसैन ने भी समुदाय में शिक्षा का अभाव बताया। उन्होंने कहा हमें अपने बच्चों को मजहबी शिक्षा के साथ-साथ उच्च स्तरीय मॉडर्न एजुकेशन भी मुहैया करानी होगी।

वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल में डेक्सा स्कैन सुविधा का उद्घाटन

स्वतंत्र सिंह भुल्लर नई दिल्ली

सफदरजंग अस्पताल में एक नई डेक्सा (डुअल-एनर्जी एक्स-रे एब्जॉर्पटियोमेट्री) स्कैन सुविधा का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया, जो अस्पताल की निदान क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। फिसर्व और यूनाइटेड वे मुंबई के सहयोगात्मक प्रयास में डॉक्टर्स फॉर यू (डीएफवाईइंडिया) द्वारा सीएसआर पहल के तहत इसका योगदान दिया गया। डॉ. संदीप बंसल, चिकित्सा अधीक्षक ने कहा कि ₹डेक्सा स्कैन सुविधा की शुरुआत सफदरजंग अस्पताल के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह उन्नत निदान उपकरण हड्डियों से संबंधित स्वास्थ्य स्थितियों का पता लगाने और उन्हें प्रबंधित करने की हमारी क्षमता में महत्वपूर्ण रूप से सुधार करेगा, जिससे हमारे रोगियों को अधिक व्यापक और सटीक चिकित्सा देखभाल मिलेगी। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीकों को लाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।₹

यह उद्घाटन केवल एक चिकित्सा उपकरण जोड़ने से कहीं अधिक है। यह रोगियों को प्रारंभिक निदान क्षमताओं के साथ सशक्त बनाने में मदद करेगा है। डीईएक्सए स्कैन निवारक स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे हम प्रारंभिक अवस्था में अस्थि घनत्व की समस्याओं की पहचान कर सकेंगे और समय पर हस्तक्षेप कर सकेंगे। यह इस बात का प्रमाण है कि कैसे सहयोगी प्रयास स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को बदल सकते हैं, ऐसा डॉ रजत जैन, अध्यक्ष, डॉक्टर्स फॉर यू ने कहा। डीईएक्सए स्कैन एक गैर-इनवेसिव डायग्नोस्टिक टूल है जो हड्डियों के स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जो निम्न के लिए महत्वपूर्ण है: ऑस्टियोपोरोसिस का प्रारंभिक पता लगाना फ्रैक्चर के जोखिम का आकलन करना हड्डियों के घनत्व में बदलाव की निगरानी करना निवारक और चिकित्सीय हस्तक्षेप का मार्गदर्शन करना इस कार्यक्रम में डॉ गीतिका खन्ना प्रिंसिपल वीएमएमसी, डॉ कपिल सूरी एएमएस, डॉ आर पी अरोड़ा एएमएस, डॉ पी एस भाटिया, डॉ कविता वाणी (कार्यवाहक एचओडी) रेडियोलॉजी, सुश्री नीता झा और फिसर्व से श्री राजीव बंसल, सीएसआर टीम, एचओडी, फैकल्टी और स्टाफ शामिल हुए।

20 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म, इंटरनेशल अवॉर्ड्स जीत चुकी 'द रैबिट हाउस' का ट्रेलर वायरल

सुषमा रानी

वैभव कुलकर्णी के निर्देशन में बनी फिल्म द रैबिट हाउस का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ और उसके बाद से ही चर्चा का विषय बना हुआ है. फिल्म पहले ही 21 इंटरनेशनल अवॉर्ड्स जीत चुकी है और खूब वाहवाही भी. फिल्म की कहानी के साथ ही इसके शानदार विजुअल्स और म्यूजिक की भी चर्चा हो रही है.

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण परिवेश में स्थापित, 'द रैबिट हाउस' एक काव्यात्मक और गहन रहस्य प्रस्तुत करती है, जो दुनिया भर के दर्शकों और आलोचकों को आकर्षित कर चुकी है. ट्रेलर लॉन्च इवेंट एक उत्साही अवसर था, जहां उद्योग और मीडिया के मेहमानों ने दृश्य और कहानी के शानदार संयोजन की सराहना की, जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया था.

यह फिल्म 20 दिसंबर, 2024 को रिलीज़ होने वाली है और यह कृष्ण पंढारे की प्रोडक्शन में पहली फिल्म है, जो वित्तीय उद्योग के अनुभवी पेशेवर हैं और 25 वर्षों से म्यूचुअल फंड व्यवसाय में कार्यरत हैं. इस नई पहल पर अपने विचार साझा करते हुए पंढारे ने कहा, ₹सिनेमा हमेशा से मेरी रुचि का विषय रहा है, और 'द रैबिट हाउस' के साथ, मैं एक ऐसी कहानी लाना चाहता था जो भारतीय संस्कृति में गहरी हो और साथ ही सार्वभौमिक रूप से संबंधित हो. यह फिल्म मेरे लिए एक सपना साकार होने जैसा है.

फिल्म की निर्माता सुनीता पंढारे को भी फिल्म बनाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सराहा गया. सेट्स पर अपनी गर्मजोशी और मार्गदर्शन के लिए जानी जाने वाली सुनीता ने कहा, ₹यह फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है, और ट्रेलर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखकर मैं अभिभूत हूं. मुझे उम्मीद है कि दर्शक इसे उतने ही गर्मजोशी से स्वीकार करेंगे जैसे हमारी टीम ने इसे किया है.

फिल्म में पद्मनाभ गायकवाड, अमित रिया और करिश्मा प्रमुख भूमिका में हैं, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और जिन्होंने बेहतरीन कहानी को जीवंत किया है. कार्यक्रम में बोलते हुए, कास्ट ने फिल्म के रिलीज़ को लेकर अपनी खुशी और इस ऐतिहासिक परियोजना का हिस्सा बनने के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की.

निर्देशक वैभव कुलकर्णी ने फिल्म के बारे में अपने विचार साझा करते हुए कहा, ₹द रैबिट हाउस एक ऐसी कहानी है जिसे बताया जाना जरूरी था, और मैं उत्साहित हूं कि इसे रिलीज से पहले ही दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है. यह संस्कृति, भावना और रहस्य का मिश्रण है, और मैं इंतजार नहीं कर सकता कि दर्शक इसे सिनेमाघरों में अनुभव करें.₹

शाम का समापन कास्ट और क्रू के साथ एक पैनल चर्चा के साथ हुआ, जिसमें फिल्म बनाने की प्रक्रिया पर जानकारी दी गई, और इसके बाद फिर से ट्रेलर की स्क्रीनिंग की गई. 'द रैबिट हाउस' भारतीय सिनेमा में थ्रिलर्स को फिर से परिभाषित करने वाली है. तैयार हो जाइए एक रोमांचक सिनेमाई अनुभव के लिए, जैसा पहले कभी नहीं हुआ.

अपराध में लगातार हो रही वृद्धि दिल्ली में बढ़ती असुरक्षा को उजागर करती है: सौरभ भारद्वाज

सुषमा रानी

नई दिल्ली, आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। ब्लू लाइन पर मेट्रो केबल चोरी होने का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुरक्षा से निपटने के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा, कि उनकी निगरानी में यहां कुछ भी सुरक्षित नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा कि "अमित शाह , दिल्ली में यह क्या हो रहा है, आज यह स्थिति हो गई है कि दिल्ली मेट्रो की केबल भी चोरी हो गई है। यदि दिल्ली मेट्रो की केबल भी सुरक्षित नहीं है जहाँ पर सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम होते हैं तो दिल्ली में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से अनुरोध करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा की दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के

लिए कुछ करो।

जहाँ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई वहीँ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा, कि दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर कीर्ति नगर से मोती नगर तक केबल चोरी हो गई है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि "यह दिल्ली है, देश की राजधानी, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे तौर पर केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में हैं, फिर भी मेट्रो केबल चोरी हो गई।"

सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि केबल चोरी तो बस एक उदाहरण है, दिल्ली में रोजाना गाड़ियां चोरी हो रही हैं, कारों के टायर चोरी किए जा रहे हैं, मोबाइल फोन छीने जा रहे हैं, चेन छीनी जा रही है और यहां तक कि बैंकों में डकैती भी हो रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के घरों से पानी के पंप चोरी हो रहे हैं, सरकार द्वारा लगाए गए मोटर और उनके तार भी चोरी हो रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, कि "दिल्ली देश की राजधानी है और फिर भी यहां अपराध में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

वीडियो के माध्यम से कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह करता हूं कि वे दिल्ली की सुरक्षा को गंभीरता से लें, दिल्ली में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने हेतु कठोर से कठोर कदम उठाए जाएं और बढ़ते अपराधों को लेकर दिल्ली की जनता के मन में इन बढ़ती सुरक्षा चिंताओं का तुरंत समाधान करें।"

1 करोड़ 15 लाख 254 लखपति दीदी बन गई हैं और बाकी दीदीयों को भी लखपति दीदी बनना है : चौहान

सुषमा रानी

नई दिल्ली! केंद्रीय ग्रामीण विकास व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कनॉट प्लेस नई दिल्ली में आयोजित सरस फूड फेस्टिवल में भाग लिया। ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री कमलेश पासवान व डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, सचिव शैलेश कुमार, अपर सचिव चरणजीत सिंह (डीएवाई.एनआरएलएम), संयुक्त सचिव (ग्रामीण आजीविका) स्मृति शरण, संयुक्त सचिव, स्वाति शर्मा व मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल थे। चौहान ने कहा कि सरस मेला बेहद सरस हो गया है। दीदीयों के द्वारा बनाये परंपरागत व्यंजनों की खुशबू दिल्लीवालों को यहां आमन्त्रित कर रही है। हमारा देश अद्भुत है अलग भाषा, अलग भेष, अलग परंपरायें और खानपान फिर भी हमारा एक है। हमारा भारत गुलदस्ते की तरह है जिसमें रंग-बिरंगे फूल खिले हुए हैं और भोजन में भी वे रंग हैं। उन्होंने अपने झारखंड दौरे का ज़क्रि करते हुए कहा कि वहा शब ए आज़म अम्बा है जिसका मतलब है स्वादिष्ट पकवान। इसे आदिवासी दीदी चलाती हैं जिसमें परंपरागत पकवान परोसे जाते हैं। चौहान ने छतीसगढ़ के गढ़कलेवा में बहनों द्वारा पारंपरिक भोजन परोसने का भी ज़क्रि किया। उन्होंने बिहार, राजस्थान, पंजाब, केरल, कर्नाटक आदि राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों की सराहना करने हुए कहा कि अपने जीवन मुल्य, अपना भोजन ये सब अदभुत हैं। इस परंपरागत भोजन की विशेषता है कि यह सेहत के लिए लाभकारी होता है। इस मेले की विशेषता यह है कि इस मेले को दीदीयां चला रही हैं। चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते मैंने मुख्यमंत्री आवास में दीदी कैफे खोला था। आज भी उन कैफे को आजीविका मिशन की दीदीयां चलाती हैं। दीदीयां जो भी काम करती हैं वह गंभीरता से करती हैं। दीदीयां यह कोशिश करती हैं कि उनके काम में कोई भी कमी न रहे। लखपति दीदी हों तो बात ही कुछ और होती है।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प महिला सशक्तिकरण है और मेरे जीवन का मिशन है कि बहन और बेटियां ग़रीब क्यों रहे? हम कहते हैं कि नारी तू नारायणी यानि अनंत शक्तियों की भंडार, जो ठान लें वह करके दिखा दे। ग्रामीण विकास मंत्रालय का यह मिशन है कि भारत की नारी को अबला नहीं रहने देंगे, सबल बनायेंगे। सबल होने पर आर्थिक सशक्तिकरण का अपना महत्व है शैक्षणिक, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक सशक्तिकरण। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से सशक्त बहन ने बताया कि सशक्त होने से घर में ही इज्जत बढ़ गई है। आज 10 करोड़ दीदीयां 90 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं जिनमें से 1 करोड़ 15 लाख 254 लखपति दीदी बन गई हैं और बाकी दीदीयों को भी लखपति दीदी बनना है। इससे भी आगे बढ़ना है और आगे का संकल्प है धीरे-धीरे आजीविका मिशन को उद्योग चलाना है। लखपति से आरंभ हुआ यह सफर करोड़पति तक जायेगा। चौहान ने शायराना अन्दाज में कहा कि ज़माना बदलना है सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मक़सद नहीं, मेरी तो हसरत है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण भारत को सशक्त करेगा, समाज को मजबूत करेगा, देश को बदलेगा। आधी आबादी को न्याय ही हमारा संकल्प है। हम पूरी ताकत से उस दिशा में आगे बढ़ेगें। सरस मेले के लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। दिल्लीवालों को भी निमंत्रण देता हूं कि वे सरस मेले में आयें।

राजू की कहानी का पर्दाफाश! यूट्यूब के एक कमेंट ने खोला राज, 8 परिवारों का बन चुका है बेटा

परिवहन विशेष न्यूज

राजू प्रकरण में इंटरनेट मीडिया ने पुलिस की जांच में अहम भूमिका निभाई। पुलिस ने राजू के सोशल मीडिया अकाउंट और यूजर्स के कमेंट्स का विश्लेषण किया जिससे उसकी असली पहचान का पता लगाने में मदद मिली। राजू ने कई परिवारों में बेटे बनकर रहने की बात कबूली है। पुलिस अब उसके द्वारा बताए गए सच की पुष्टि कर रही है।

साहिबाबाद। इंटरनेट मीडिया की दुनिया बहुत बड़ी होती है, इसका उदहारण राजू प्रकरण में देखने को मिला। प्रारंभ में राजू ने पुलिस को सच नहीं बताया। ऐसे में पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर राजू के संबंध यूजर द्वारा किए गए तरह-तरह के कमेंटों का संज्ञान लिया।

सूत्रों मुताबिक कमेंटों के जरिये ही पुलिस राजू से सच उगलवाने में सफल हुई। हालांकि अभी उसके द्वारा बताए गए सच की अधिकारिक तस्दीक करनी बाकी रह गई है। पुलिस रविवार से राजू से पूछताछ कर रही है। शुरूआत में वह पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा।

पुलिस ने कराया डीएनए टेस्ट

पुलिस को यह भी संशय था कि राजू शहीद नगर के तुलेराम का बेटा हो भी सकता है। जिस वजह से पुलिस ने उसका डीएनए टेस्ट कराया। टीएनए टेस्ट से केवल इतना पता चल सकता है कि यह तुलेराम का बेटा है या नहीं लेकिन पुलिस को राजू की तह तक जाना था।

जब राजू (raju real story) ने सच नहीं बताया तो पुलिस ने इंटरनेट मीडिया के जरिये उसकी सच्चाई का पता लगाना शुरू किया। राजू की कहानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म प्रसारित हो रही है। लोग वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं।

राजू ने बताया उसका असली नाम इंद्रराज

पुलिस (ghaziabad police) कमेंटों को खंगालने में जुट गई। कई लोगों ने कमेंट कर दावा किया कि राजू ने कई अन्य परिवारों में बेटा बनकर रहा है। ऐसे में पुलिस ने कमेंट करने वालों से सहयोग लिया। यूजर ने कमेंट कर यह भी दावा किया गया कि वह श्री गंगानगर का रहने वाला है।

इसके बाद पुलिस (sahibabad police) ने उसके परिवार से बात की। इसके बाद पुलिस ने परिवार के व्यक्ति का नाम लेकर राजू से पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी बयां कर दी। राजू ने बताया कि उसका असली नाम इंद्रराज है।

उसके परिवार में माता-पिता, एक भाई व दो बहनें हैं। पिता का नाम चुन्नीलाल है। वर्ष 2011 में चुन्नीलाल ने उसे घर से निकाल दिया था।घर से निकलने के बाद उसने अपना नाम राजू रख लिया था। इसके बाद वह आठ परिवारों में बेटा बनकर रहा। इंटरनेट मीडिया पर राजू के संबंध में किए गए कमेंट पर पुलिस नजर रख रही है। जो तथ्य सामने आए हैं पुलिस उनकी तस्दीक कर रही है। शनिवार तक पुलिस राजू की कहानी का पर्दाफाश कर सकती है।

निमिष पाटील, पुलिस उपायुक्त, ट्रांस हिंडन।

लाखों की वसूली का मामला, बिजली विभाग में चल रहा था बड़ा 'खेल'; सच्चाई जान हर कोई हैरान

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद के साहिबाबाद में वसुंधरा सेक्टर-चार और तीन की झुग्गी-झोपड़ियों में बिजली विभाग द्वारा बिना मीटर के बिजली आपूर्ति कर हर महीने लाखों रुपये वसूले जा रहे हैं। हर झुग्गी से 200 से 1000 रुपये तक बिल के नाम पर वसूली की जाती है। रुपये देने के बाद भी कोई रसीद नहीं दी जाती। इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं।

साहिबाबाद। गाजियाबाद के साहिबाबाद में वसुंधरा सेक्टर-चार व तीन की झुग्गी-झोपड़ियों में विद्युत निगम द्वारा बिना मीटर के ही बिजली आपूर्ति कराकर हर माह लाखों रुपये की वसूली का मामला सामने आया है।

प्रत्येक झुग्गी से दो सौ से एक हजार रुपये तक बिल के नाम पर वसूले जाते थे। रुपये देने के बाद लोगों को किसी तरह की रसीद भी नहीं दी जाती थी। दैनिक जागरण टीम की झुग्गियों में रहने वाले लोगों से बृहस्पतिवार को हुई बातचीत में ये बड़ा मामले सामने आया। वहीं, अधिकारियों ने मामले की जांच कराने की बात कही है।

झुग्गियों को तोड़ने का कार्य शुरू किया

सेक्टर-4 में आवास विकास परिषद की खाली जमीन में मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के लोगों द्वारा रहने के लिए एक हजार से अधिक झुग्गियां बनाई गई हैं। बुधवार को आवास विकास परिषद की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में सुबह करीब 10:30 बजे झुग्गियों को तोड़ने का कार्य शुरू किया।

इस दौरान झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने अपनी परेशानी बताने के साथ ही बड़ा खुलासा भी किया। लोगों से झुग्गी बनाने के एवज में किसी के द्वारा रुपये लेने की बात पूछी गई तो उन्होंने किसी को भी पैसे देने से मना किया।

यहां कोई मीटर की सुविधा नहीं

इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि रात में अंधेरे में रहते हैं या बिजली का कोई इंतजाम है। उन्होंने बताया कि झुग्गी होने के कारण यहां कोई मीटर की सुविधा नहीं हैं। विद्युत निगम के कर्मी आते हैं वह जो भी रुपये मांगते हैं दे देते हैं। अगर रुपये नहीं देते हैं तो तार काटकर ले जाते हैं।

इससे मजबूरी में बिजली उपयोग करने के एवज में 200, 300, 500 व एक हजार रुपये लेते हैं। यानी करीब एक हजार से अधिक झुग्गियों से हर माह कई लाख रुपये की वसूली की जा रही है।

लाइट जलाने, वाशिंग मशीन व फ्रीज चलाने वालों से लेते हैं 1 हजार

जो लोग झुग्गियों में लाइटों के साथ ही वाशिंग मशीन व फ्रीज चलाते थे उनसे हर माह एक हजार रुपये, केवल बल्ब जलाते थे उनसे हर माह 200 से 300 रुपये और वाशिंग मशीन व फ्रीज में से केवल एक उपकरण चलाते हैं उससे 500 रुपये लिए जाते हैं। रसीद मांगने पर बिना मीटर लगे रसीद देने से मना कर देते हैं।

झुग्गी के पीछे 11 हजार केवी लाइन से डाले गए हैं तार

झुग्गियों के पीछे की साइड 11 हजार केवी की लाइन जा रही है। इसी लाइन पर कटिया डालकर झुग्गियों में बिजली आपूर्ति की जा रही है। इसमें यह भी मामला सामने आया कि खुलासा होने के डर से कई बार वह दिन में तार हटा जाते थे।

बल्लियों पर तार लटकाकर झुग्गियों में ले जाए जा रहे

मौके पर बल्लियों पर तार लटके मिले। इन तारों को झुग्गियों-झोपड़ियों के अंदर ले जाया जा रहा था। तार भी कुछ ऊंचाई पर ही लटके हुए थे। जगह-जगह तार भी नंगे थे। इससे बड़ा हादसा हो सकता था।

इस तरह होती है वसूली

केवल लाइट जलाने के 200 रुपये

लाइट, वाशिंग मशीन व फ्रीज चलाने के 1000 रुपये

लाइट व वाशिंग मशीन या फ्रीज चलाने के 500 रुपये

मुख्य अभियंता का इन बिंदुओं पर जांच कराने का दावा

-झुग्गियों में बिजली आपूर्ति के एवज में कोई रैकेट तो कार्य नहीं कर रहा था।

-कोई संविदा कर्मी तो वसूली नहीं करा रहा था।

-इसमें विद्युत निगम का कोई अधिकारी तो शामिल नहीं है।

-वसूली करने वाले बाहरी लोग तो नहीं हैं।

विद्युत निगम के कुछ लड़के आते थे। वह झुग्गी तक तार भी खुद डालकर देते थे। इसके बाद वह हर माह 500 रुपये लेते थे। नहीं देने पर कनेक्शन काट दिया जाता था। - अक्षय, झुग्गी निवासी

बीते कई वर्ष से यहां रह रहा हूं। विद्युत निगम पहले सौ रुपये वसूलता था। जब से बैटरी वाली गाड़ी आइ है तब से 500 से एक हजार लेते हैं। कोई रसीद नहीं मिलती है। - लल्ला, झुग्गी निवासी

करीब 20 वर्ष से यहां रह रहे हैं। अब इतनी सर्दी में हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। बिजली के लिए हर माह 200 रुपये देते थे। रुपये नहीं देने पर कनेक्शन काट दिया जाता था। - परमिला, झुग्गी निवासी

यहां एक हजार से अधिक झुग्गियां हैं। प्रत्येक झुग्गी से पांच से एक हजार रुपये तक लिए जा रहे हैं। हम भी हर माह 500 रुपये देते हैं। वसूली के लिए विद्युत निगम का कर्मी आता है। - राम प्रवेश, झुग्गी निवासी

अगर झुग्गियों में बिना मीटर बिजली आपूर्ति कराकर कोई वसूली कर रहा है तो इसकी जांच की जाएगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - दीपक अग्रवाल, मुख्य अभियंता, विद्युत निगम जोन-तीन

किसान फिर गिरफ्तार, गांव-गांव तक फैली आक्रोश की चिंगारी

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा पुलिस ने एक बार फिर से 34 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। इससे आंदोलन की चिंगारी गांव-गांव में फैल गई है। किसान 10 प्रतिशत आबादी भूखंड भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ और हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने दो दिसंबर को दिल्ली कूच का प्रयास किया था लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया था।

ग्रेटर नोएडा। किसान आंदोलन में बुधवार देर रात बड़ा मोड़ आ गया। पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो प्वाइंट के नजदीक रात में धरना दे रहे 34 किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ज्यादातर किसान नेता पुलिस गिरफ्तारी से बचकर भूमिगत हो गए।

पुलिस की देर रात में हुई कार्रवाई से आंदोलन की चिंगारी गांव-गांव में फैल गई है। गांवों में किसानों के छोटे-छोटे समूह बैठक कर आगे की रणनीति का इंतजार कर रहे हैं। नेताओं का संदेश मिलते ही किसान एकत्र होकर आंदोलन को आक्रामक मोड़ देंगे।

क्या है किसानों की मांगें ?

दस प्रतिशत आबादी भूखंड, भूमि अधिग्रहण कानून के सभी लाभ देने व हाई पावर कमेटी की किसानों के हक में दी गई सिफारिशों को लागू करने के लिए 25 नवंबर से किसान संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में दस किसान संगठन महापड़ाव कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण पर महापड़ाव के बाद किसानों ने दो दिसंबर को दिल्ली कूच का प्रयास किया था, लेकिन महामाया फ्लाईओवर के नजदीक पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया।

किसानों की मुख्य सचिव से एक सप्ताह में वार्ता का आश्वासन दिया, इसके बाद किसान दलित प्रेरणा स्थल पर महापड़ाव कर धरने पर बैठ गए, लेकिन मंगलवार को पुलिस ने प्रमुख नेताओं समेत 123 किसानों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके विरोध में बुधवार को किसानों ने यमुना एक्सप्रेस वे के जीरो प्वाइंट पर महापंचायत हुई।

अधिकारियों ने किसानों की मांग पर शाम को करीब चार बजे किसान नेताओं को जेल से रिहा कर दिया। इसके साथ ही हाई पावर कमेटी की सिफारिश इसी माह लागू कराने और अन्य मांगों को शासन स्तर से निस्तारण करने का आश्वासन दिया। लेकिन किसान जीरो प्वाइंट पर ही रात में धरने पर बैठे रहे। देर रात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुखबीर खलीफा और सोरन प्रधान समेत 34 किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

इसके बाद अन्य नेता भूमिगत हो गए। उनकी तलाश में पुलिस चप्पा चप्पा छान रही है। नेताओं ने पुलिस को चकमा देने के लिए अपने मोबाइल फोन भी बंद कर लिए हैं। गांव-गांव किसान पंचायत कर आगे की रणनीति का संदेश मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 12 बजे किसान एक बार फिर जीरो प्वाइंट पर एकत्र हो सकते हैं।

ग्रेटर नोएडा : जीरो पॉइंट नजदीक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर तैनात पुलिसकर्मी

किसान नेता डॉ. रुपेश वर्मा का कहना है कि पुलिस ने वादा खिलाफी की है। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को 4 दिसंबर की रात में गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने दमन उत्पीड़न करते हुए अपने ही वादे से मुकरते हुए सुखबीर खलीफा एवं सोरन प्रधान सहित 15-20 किसानों को जेल भेज दिया है।

किसान सभा के जिला महासचिव जगबीर नंबरदार जिला उपाध्यक्ष गवरी मुखिया को अन्य 10 लोगों के साथ रात में ही घर से पकड़ कर जेल भेज दिया है। संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस का कहर रात भर जारी रहा। उदल आर्य के घर के गेट को तोड़ते हुए उनकी पत्नी को भी थाने में ले जाकर बिठा दिया। किसान दमन और उत्पीड़न से पीछे हटने वाले नहीं है।

शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन नागरिकों का हक है। योगी सरकार ने किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन का दमन करने की कोशिश की है। सरकार पूरी तरह पूंजी पति परस्त एवं किसान विरोधी है। किसानों की जमीन पर नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना सिटी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। उन्हें उनका हक पिछले 50 सालों से नहीं मिला है । उनके विकसित आबादी प्लाट अभी तक नहीं मिले हैं।

प्राधिकरण के अफसर भ्रष्टाचार कर किसान के हिस्से की जमीन को भी खा गए हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 10 परसेंट के प्लाट नहीं दिए गए हैं। जिले में 3.50 लाख से अधिक किसान 10% के प्लॉट की मांग से प्रभावित हैं इसके बावजूद सरकार किसानों के दमन और उत्पीड़न पर लगी हुई है। आज किसान हजारों की संख्या में फिर से जीरो प्वाइंट पर इकट्ठा होंगे। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे।

उधर, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक्स पर कहा गया है कि छह दिसंबर को भारत रत्न बाबा साहेब आंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। विभिन्न संगठन बाबा साहेब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए धरने प्रदर्शन कर सकते हैं।

अराजक तत्व माहौल खराब करने का कुत्सित प्रयास कर सकते हैं। यह तिथि काफी संवेदनशील है। दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों के महापड़ाव को लेकर सतर्क है पुलिस किसान एक बार फिर दलित प्रेरणा स्थल पर महापड़ाव कर सकते हैं। पुलिस इसे रोकने के लिए पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है।

दिल्ली सल्तनत पर बार-बार क्यों करते हैं किसान चढ़ाई?

डॉ. रमेश ठाकुर

दरअसल, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान संगठनों ने एक बार फिर दिल्ली पर चढ़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ऐसा करने से उन्हें बलपूर्वक बॉर्डरों पर ही रोका गया है। पर, हालात दिल्ली-एनसीआर के एक बार फिर बिगड़ते दिखाई पड़ने लगे हैं।

अन्नदाताओं की समस्याओं का समाधान आखिर कब होगा? क्या उनकी मांगे भविष्य में कभी पूरी हो भी पाएंगी या नहीं? केंद्र में सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, हर दौर में यही सब कुछ देखने को मिलता है। कमोबेस, सरकारों का रवैया सदैव एक जैसा ही रहता है। इसलिए एकाएक किसी सरकार को दोषी ठहराना किसी टिप्पणीकार के लिए बेईमानी सा होता है। किसान आंदोलनों से जो समस्याएं उपजती हैं, उसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आमजन ही भुगतते हैं। समस्याएं किस कदर पनपती हैं इस ओर शायद किसी का भी ध्यान नहीं जाता। मरीज, छात्र, राहगीर, दैनिक कर्मी तो बेहाल होते ही हैं, रोजमर्रा के क्रियाकलाप भी रुक जाते हैं। दो दिसंबर को भी यही हुआ, जब किसान उत्तर प्रदेश के एक छोर से चले, तो सड़कों पर दौड़ने वाले तेज वाहनों के पहिए थम गए। क्या मरीज, क्या नौकरीपेशा, सभी के पैर अपने जगह रूक गए।

दरअसल, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान संगठनों ने एक बार फिर दिल्ली पर चढ़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ऐसा करने से उन्हें बलपूर्वक बॉर्डरों पर ही रोका गया है। पर, हालात दिल्ली-एनसीआर के एक बार फिर बिगड़ते दिखाई पड़ने लगे हैं। इस दफे भी किसानों के तेवर उग्र दिख रहे हैं। अन्नदाता लंबा आंदोलन करने के मूड़ में दिखाई पड़ते हैं। इतना तय है, अगर उनकी समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं हुआ, तो हालात पिछले किसान आंदोलन जैसे बनने में वक्त नहीं लगेगा। किसान केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को बीते एक महीने से अल्टीमेटम दे रहे थे कि उनकी मांगे मानी जाएं, उनसे बात करे कोई जिम्मेदार व्यक्ति, जिससे दोनों पक्ष बैठकर कोई हल निकाल सकें। लेकिन उनकी बातों को हुकूमती स्तर पर एक बार भी अनसुना और अनदेखा किया गया।

दिल्ली पहुंचने के लिए गौतमबुद्ध नगर से करीब 50,000 से अधिक किसान सोमवार सुबह यानी दो तारीख को नोएडा महामाया फ्लाईओवर के पास एकत्रित हुए, फिर उन्होंने दिल्ली कूच का प्लान किया, हालांकि तत्काल रूप से तो पुलिस ने उनकी योजना को विफल कर दिया है। लेकिन किसान बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं, वह किसी भी सूरत में दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। उनको लगता है संसद का शीत सत्र चालू है। पूरी हुकूमती मशीनरी इस समय एक साथ है, उनकी बातें आसानी से पहुंच सकती है। पर, ऐसा होता दिख नहीं रहा। केंद्र सरकार इतनी आसानी से सबकुछ मान लेगी, ऐसा भी दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए किसान भी काफी उग्र हैं। अपने साथ लंबे आंदोलन को करने के लिए तामझाम लेकर पहुंच हैं। राशन, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, गैस सिलेंडर, तंबू आदि है उनके पास।

किसानों ने दिल्ली मार्च का प्लान अचानक से ही बनाया। पहले की प्री-प्लान नहीं थी। क्योंकि किसान अपनी विभिन्न मांगो को लेकर

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण पर पिछले कुछ दिनों से धरनागत थे। उनकी प्रमुख मांगे हैं, उन्हें ज़मीन के बदले 10 पर्सेंट निर्मित प्लॉट और 64 पर्सेंट बढ़ा हुआ जमीन का शेष मुआवज़ा दिया जाए। साथ ही जितने किसान जमीन छिन जाने से भूमिहीन हुए हैं, उनके परिवार के बच्चों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई न कोई रोजगार जैसी वैकप्लिक व्यवस्थाएं की जाएं, इसके अलावा एमएसपी गारंटी कानून लागू करें। फसलों की कीमतें डबर हों, खाद, बीज व कीटनाशक दवाईयों के रेट कम किए जाएं जैसी पुरानी मांगे भी उनकी बरकरार हैं। इस वक्त मंड़ियों में धान की खरीद में जो घटतौली हो रही है उसे तुरंत रोका जाए। ये मांगे ऐसी जिसे शायद ही सरकारें मांगे।

प्रतीत ऐसा होता है कि ये किसान मूवमेंट भी बडा रूप ले सकता है। अभी तक गनीमत ये समझी जाए, इस मोर्चे में सिर्फ दर्जन भर ही किसान संगठन शामिल हुए हैं। हालांकि बाहर से करीब सौ से ज्यादा किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त है। मोर्चे को रोकने को अगर कोई जल्द विकल्प नहीं निकाला गया, तो अन्य किसान संगठन भी कूदने में देर नहीं करेंगे। हांलाकि सोमवार को किसान मोर्चे को देखते हुए नोएडा ट्रैफ़िक पुलिस और दिल्ली पुलिस की ओर से एडवाइजरी की गई जिसमें कालिंदी कुंज बॉर्डर, यमुना एक्सप्रेस-वे और डीएनडी बॉर्डर से बचने की लोगों को सलाह दी गई, क्योंकि इन जगहों पर मोर्चे का असर व्यापक रूप से देखने को मिला। लोग अनचाई परेशानी से जूझते दिखाई पड़े, स्कूली बच्चों भी जाम में फंसे रहे, एमबूलेंस भी नहीं निकल पाईं। नौकरीपेशा समय से अपने कार्यालयों में नहीं पहुंच पाए। ये हालात ऐसे ही बने रहेंगे, जब तक ये मूवमेंट चलता रहेगा।

किसान मूवमेंट शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही राजनीति भी आरंभ हो गई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया। कांग्रेस ने कहा दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, वाटर कैनन, दंगा नियंत्रण गाड़ियां और अमित शाह की पूरी पुलिस तैनात की गई। ऐसा प्रतीत होता है जैसे की उनको किसी आंतकवादी को रोकना या पकड़ना हो? किसान भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवज़ा और फसल के सही दाम की मांग लेकर दिल्ली आकर सोती सरकार को जगाना चाहते हैं इसमें बुरा क्या है? वहीं, आम आदमी पार्टी की ओर से बयान आया जिसमें कहा गया कि राष्ट्र की राजधानी किसी की बपौती तो है नहीं? फिर किसान क्यों नहीं आ सकते? प्रधानमंत्री पर भी उन्होंने हमला किया। बोले, किसानों पर बर्बरता के नए आयाम रच रहे हैं प्रधानमंत्री। उनके दिल में अन्नदाताओं के लिए रत्ती भर सम्मान नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि किसान अपनी जायज मांगों को लेकर दिल्ली आना चाहते हैं, उन्हें आने देना चाहिए, उनपर वाटर कैनन का प्रयोग करना गलत है। दरअसल, ऐसे मौकों पर विपक्ष का बिना सोचे समझे कूद पड़ना, 'आग में घी डालने' का काम कर जाता है। जबकि, उन्हें केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर विकल्प और समाधान की ओर ध्यानाकर्षण करवाना चाहिए। ताकि सरकार आंदोलनकारियों से बात करने पर विवश हो? पर, दुर्भाग्य ऐसा हो नहीं पाता और न ही विपक्ष ऐसा प्रयास करता है।

सदस्य, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD), भारत सरकार!

– :सौजन्य :–

ईवी ड्राइव द फ्यूचर

EV

Drive the Future

ईवीएक्सपो सबसे बड़ी उपलब्धि उत्कृष्टता के 10 वर्ष

परिवहन विशेष न्यूज

जब कोई स्व-वित्तपोषित कंपनी समय के साथ संघर्ष या बाधाओं की चिंता किए बिना आगे बढ़ती है, तो वह अपने लिए एक बेंचमार्क स्थापित करती है। यह कई स्टार्ट-अप और उद्यमियों के लिए एक स्पष्ट संदेश के साथ एक जीवंत उदाहरण बन जाती है।

सही दृष्टिकोण और सही लोगों के साथ, कोई भी बाधा आपको अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं रोक सकती।

तमाम उतार-चढ़ाव, कठिनाइयां और अराजकता (कोविड-19) के बीच, ईवीएक्सपो एक ठोस चट्टान की तरह खड़ा रहा और अपने एक्जीबिटर्स को मजबूत समाधान प्रदान करना कभी बंद नहीं किया।

परिणामस्वरूप, अब ईवीएक्सपो 10वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा हैं। यह एक ऐसा मील का पत्थर है जिसका सपना कई शुरुआती (कॉरपोरेट फर्म के सीईओ और निदेशक) शुरू करते समय देखते हैं, लेकिन केवल कुछ ही इसे पार कर पाते हैं।

ईवीएक्सपो के संयोजक राजीव अरोड़ा का कहना हैं कि इन 10 सालों में ईवीएक्सपो में कई नए निर्माता और स्टार्टअप प्रदर्शक बनकर आए हैं और ब्रांड बनकर ईवी इंडस्ट्री और लोगों के दिलों में अपनी पहचान बनाई है। आज भी लोग ईवीएक्सपो में आकर ईवी इंडस्ट्री को करीब से समझने और कंपनियों के उत्पादों को देखने का इंतजार करते हैं। ईवीएक्सपो ने सभी ईवी निर्माताओं को देश में अपना नाम और काम बनाने का सुनहरा मंच दिया है।

उन्होंने कहा कि आप सभी एक्जीबिटर्स के बिना, यह उपलब्धि इतनी सुखद नहीं होती। इसलिए सभी को विशेष बधाई।

इलेक्ट्रिक वाहनों की घटती मांग से जर्मनी में कारों की बिक्री में गिरावट

परिवहन विशेष न्यूज

बुधवार, 04 दिसंबर को आधिकारिक आंकड़ों से पता चला कि जर्मनी में नवंबर में नई कारों की बिक्री में गिरावट आई है, जिसका कारण इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में भारी गिरावट है, जो कि इलेक्ट्रिक वाहनों के संक्रमण की समस्या का एक और संकेत है।

केबीए संघीय परिवहन प्राधिकरण ने बताया कि पिछले महीने यूरोप के सबसे बड़े ऑटो बाजार में कुल 244,544 वाहन पंजीकृत हुए, जो एक वर्ष पहले की तुलना में आधा प्रतिशत कम है।

अक्टूबर में हुई बढ़ोतरी के अलावा, जर्मनी में नई कारों की बिक्री में कई महीनों से गिरावट का रुख बना हुआ है।

नवंबर में बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में लगभग 22 प्रतिशत की गिरावट आई, जिसमें ई.वी. की हिस्सेदारी कुल बिक्री का लगभग 14 प्रतिशत रही - जो 2023 के औसत से काफी कम है।

कई वर्षों की वृद्धि के बाद, 2023 के अंत में सरकारी सब्सिडी समाप्त होने के बाद से जर्मनी में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में कमी आ रही है।

कंसल्टेंसी फर्म ईवाई के विश्लेषक कॉन्सटेनटिन गैल ने कहा कि सब्सिडी खत्म होने से ₹बाजार की सारी गति खत्म हो गई।₹

₹इलेक्ट्रिक कारें बाजार में अपनी हिस्सेदारी खो रही हैं, भले ही नए और आकर्षक कीमत वाले मॉडल बाजार में आ रहे हैं।₹

जर्मनी में बिक्री में गिरावट यूरोप में व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाती है, जहां दहन इंजन से दूरी की प्रक्रिया अपेक्षा से धीमी गति से आगे बढ़ रही है।

गैल के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों की ऊंची कीमतें, कभी-कभी महंगी चार्जिंग, चार्जिंग के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और अपर्याप्त ड्राइविंग रेंज, ये सभी कारण हैं, जिनके कारण उपभोक्ता जीवाश्म ईंधन वाले मॉडलों को

छोड़ने को तैयार नहीं हैं।

लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी आएगी, क्योंकि निर्माता 2025 में लागू होने वाली यूरोपीय संघ की सख्त उत्सर्जन आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश में लगे हैं।

गैल ने कहा कि नए लक्ष्य केवल तभी पूरे किए जा सकते हैं, जब बिकने वाली नई कारों में से एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक हो, जिससे निर्माता ₹अपनी कीमतों में उल्लेखनीय कमी करें या बहुत अनुकूल वित्तपोषण शर्तें पेश करें।₹

जर्मन ऑटो क्षेत्र कई समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें घरेलू स्तर पर तथा चीन जैसे प्रमुख विदेशी बाजारों में कमजोर मांग से लेकर उच्च विनिर्माण लागत तक शामिल है।

कार दिग्गज कंपनी वोक्सवैगन लागत में कटौती के लिए पहली बार जर्मनी में कारखाने बंद करने पर विचार कर रही है, जबकि प्रतिद्वंद्वी बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज-बेंज ने भी मुनाफे में गिरावट की सूचना दी है और खराब स्थिति की चेतावनी दी है।

तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम का लक्ष्य इलेक्ट्रिक बसों में बदलाव

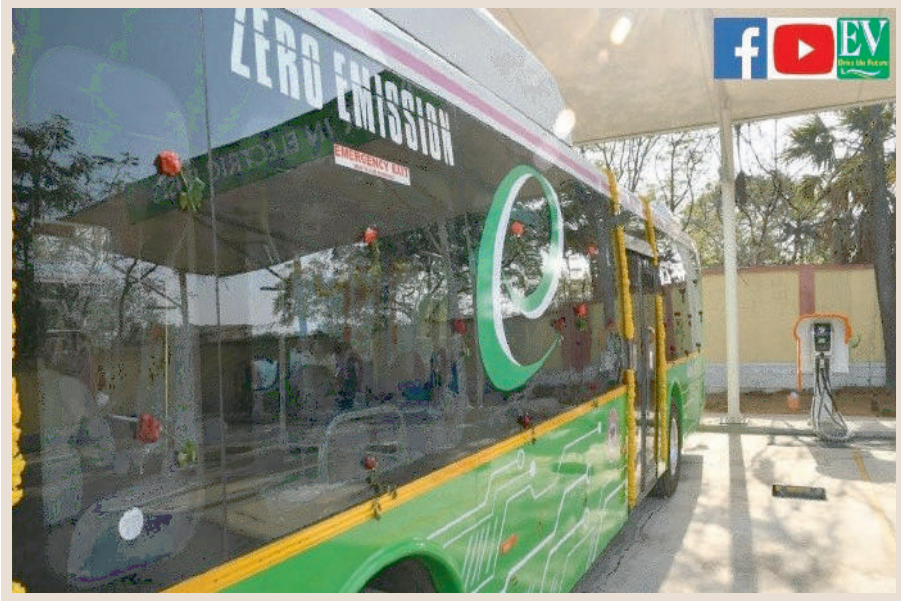

परिवहन विशेष न्यूज

तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम हैदराबाद ग्रेटर जोन में अपने पूरे डीजल बेड़े को 2,800 इलेक्ट्रिक बसों से बदलने जा रहा है, जो एक टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल वाहन प्रदूषण को कम करने और यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के लिए राज्य की नीतियों के साथ तालमेल बिठाने के निगम के प्रयासों का हिस्सा है।

टीजीएसआरटीसी के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वीसी सज्जनार के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष महालक्ष्मी योजना का सफल कार्यान्वयन भी देखा गया। महिला यात्रियों को 110.93 करोड़ शून्य-किराया टिकट जारी किए गए, जिससे यात्रा लागत में 3,747.19 करोड़ रुपये की बचत हुई।

अपनी हरित पहल के तहत, हैदराबाद, करीमनगर और निज़ामाबाद में 251 इलेक्ट्रिक बसें सेवा में लगाई गईं, साथ ही मार्च 2025 तक इंट्रा-सिटी और इंटर-सिटी सेवाओं के लिए अतिरिक्त 3,599 इलेक्ट्रिक बसों की योजना बनाई गई है।

अपनी हरित पहल के तहत, हैदराबाद, करीमनगर और निज़ामाबाद में 251 इलेक्ट्रिक बसें सेवा में लगाई गईं, साथ ही मार्च 2025 तक इंट्रा-सिटी और इंटर-सिटी सेवाओं के लिए अतिरिक्त 3,599 इलेक्ट्रिक बसों की योजना बनाई गई है।

हीरो इलेक्ट्रिक के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई की जरूरत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने एसएफआईओ से कहा

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार, 04 दिसंबर को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को अपनी जांच स्थगित करने और हीरो इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी फेम II योजना के तहत सब्सिडी के कथित दुरुपयोग को लेकर कंपनी के साथ अपने विवाद को सुलझाने पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक रोक लगाने को कहा।

10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2019 में शुरू की गई फेम II योजना, ईवी अपनाने और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए दोपहिया वाहन कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करती है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हीरो इलेक्ट्रिक ने न्यायमूर्ति सी.डी. सिंह की पीठ को बताया कि वह मंत्रालय के साथ विवाद को सुलझाने के लिए तैयार है, जिसने फेम-II मानदंडों के कथित उल्लंघन का हवाला देते हुए कंपनी को भुगतान किए गए 133 करोड़ रुपये ब्याज सहित वापस मांगे हैं।

इसे स्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने हीरो इलेक्ट्रिक को 12 दिसंबर तक मंत्रालय के संबंधित अधिकारी से संपर्क करने और संभावित समाधान तलाशने का प्रस्ताव देने का निर्देश दिया। अदालत ने मंत्रालय को प्रस्ताव पर विचार करने और 20 दिसंबर को अगली सुनवाई के दौरान समाधान पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

कंपनी और उसके निदेशक नवीन मुंजाल ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर कंपनी के खिलाफ एसएफआईओ जांच का निर्देश देने वाले कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के आदेश को चुनौती दी।

एसएफआईओ ने हीरो इलेक्ट्रिक सहित तीन इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं की पहचान की है, जो कथित तौर पर फेम II योजना के तहत 297 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्राप्त करने में धोखाधड़ी में शामिल हैं।

कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा और अधिवक्ता अनुराधा दत्त ने आरोपों से इनकार किया और पहले से की गई बिक्री के लिए लंबित 570 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी करने की मांग की।

ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ने 33.5 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता के साथ भारत के ईवी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को दिया बढ़ावा

परिवहन विशेष न्यूज

ब्रिटेन की विकास वित्त संस्था और प्रभाव निवेशक ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट (बीआईआई) ने आज भारत के इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के लिए 33.5 मिलियन डॉलर की नई प्रतिबद्धताओं की घोषणा की। यह निवेश उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने और ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने के लिए बीआईआई की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

प्रतिबद्धताओं में एवरेस्ट फ्लीट को 15 मिलियन डॉलर का ऋण वित्तपोषण, टीआई क्लीन मोबिलिटी में 15 मिलियन डॉलर का इक्विटी निवेश और वेकमोकॉन को 3.5 मिलियन डॉलर की इक्विटी प्रतिबद्धता शामिल है। वे भारत में ईवी अपनाने की बहुमुखी चुनौतियों का समाधान करने के लिए उद्योग मूल्य श्रृंखला के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

18,500 से ज़्यादा कारों के बेड़े वाली भारत की अग्रणी फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी एवरेस्ट फ्लीट, BII के फंडिंग का इस्तेमाल अपने इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए करेगी। इसके लिए कंपनी 2,100 इलेक्ट्रिक वाहनों के मौजूदा बेड़े में 1,300 नए इलेक्ट्रिक वाहन जोड़ेगी। इस पहल से छह प्रमुख शहरों मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई में ड्राइवरों के लिए रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे।

टीआई क्लीन मोबिलिटी भारत का सबसे व्यापक ईवी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए समर्पित है। यह तीन पहिया वाहनों, ट्रकों, छोटे वाणिज्यिक वाहनों और ट्रैक्टरों सहित ईवी के डिजाइन और निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। जीईएफ के साउथ एशिया ग्रोथ फंड III के माध्यम से बीआईआई के सह-निवेश का उपयोग कम कार्बन वाहनों के निर्माण को बढ़ाने और बड़े पैमाने पर समावेशी नौकरियों के निर्माण के लिए पूंजी आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा।

बेहतर, सुरक्षित और स्मार्ट ईवी के निर्माण को बढ़ाने के लिए, वेकमोकॉन बैटरी प्रबंधन प्रणाली, मोटर नियंत्रक, वाहन इंटेलिजेंस मॉड्यूल, चार्जर आदि जैसे महत्वपूर्ण घटकों को डिज़ाइन करता है। यह ईवी इकोसिस्टम के खिलाड़ियों को डेटा-संचालित जानकारी भी प्रदान करता है, जिसमें फाइनेंसर और ग्राहक शामिल हैं, ताकि ईवी को अधिक सुलभ बनाया जा सके। दिल्ली स्थित इस कंपनी ने भारतीय

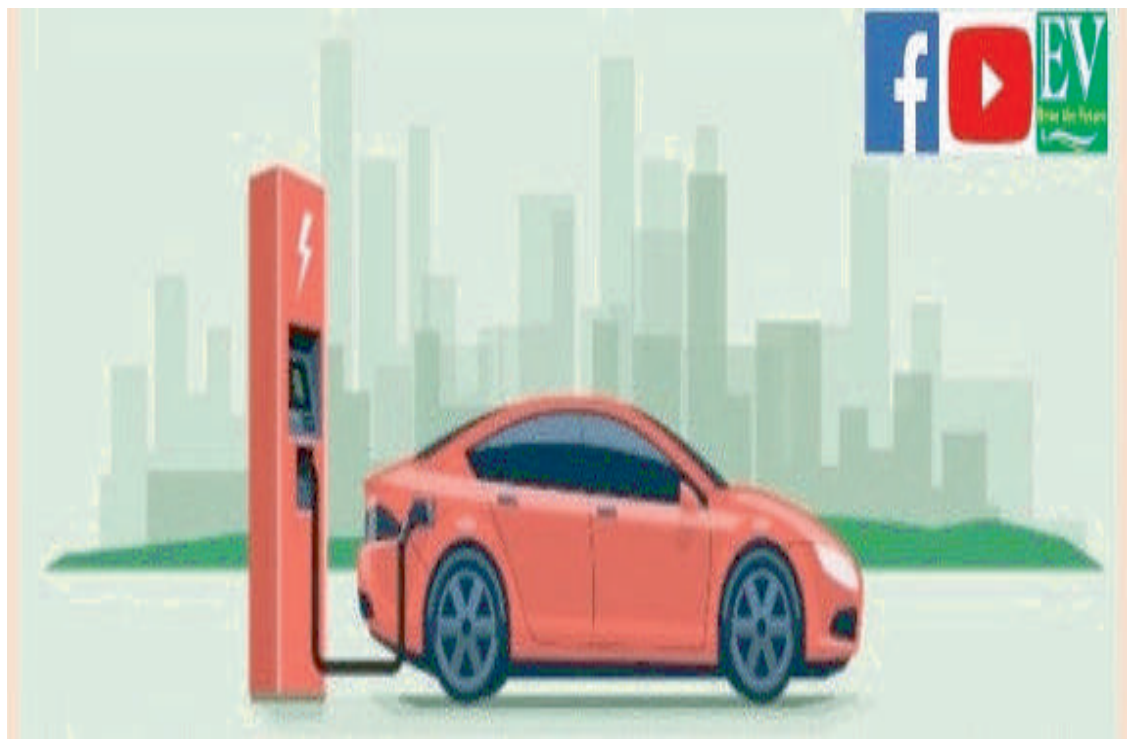

सड़कों पर 60,000 से अधिक कारों को सक्षम किया है। बीआईआई, ईआइएफ और ब्लूम वेंचर्स से फंडिंग के साथ, यह अपनी R&D क्षमताओं को बढ़ाएगा और वाणिज्यिक ईवी बाजार में विस्तार करेगा।

भारत को गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने और 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए तत्काल अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की आवश्यकता है। भारत सरकार ने ईवी30@30 पहल के तहत 2030 तक 30 प्रतिशत ईवी पैठ का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में, भारत में कुल वाहन बिक्री में ईवी का हिस्सा लगभग 6.4 प्रतिशत है।

हालाँकि, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें उच्च प्रारंभिक लागत, सीमित चार्जिंग बुनियादी ढांचा और किफायती वाहन वित्तपोषण विकल्पों की कमी शामिल है।

सैली टेलर, निदेशक विकास, जलवायु, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा, ₹स्थायी गतिशीलता के प्रति भारत का महत्वाकांक्षी अभियान हरित भविष्य के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का एक प्रेरक प्रमाण है। भारत के शून्य उत्सर्जन वाहन क्षेत्र में प्रगतिशील और अभिनव कंपनियों के लिए ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का समर्थन जलवायु परिवर्तन जैसी साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमारे देशों के बीच गहरी साझेदारी को दर्शाता है। साथ मिलकर, यूके-भारत स्वच्छ हवा, एक संपन्न भविष्य की गतिशीलता पारिस्थितिकी तंत्र और एक अधिक टिकाऊ कल के लिए मार्ग बना रहे हैं।"

बीआईआई में प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार के प्रबंध निदेशक और प्रमुख अभिनव सिन्हा ने कहाः"भारत में ईवी एक नया क्षेत्र बना हुआ है। यहीं पर बीआईआई, यूके के डीएफआई के रूप में, भारत की ऊर्जा परिवर्तन और डीकार्बोनाइजेशन यात्रा में योगदान देने के लिए अग्रणी कंपनियों का समर्थन कर सकता है। ईवी क्षेत्र में निवेश करने का हमारा दृष्टिकोण ईवी और उसके पुर्जों के निर्माण से कहीं आगे जाता है; इसका उद्देश्य लोगों को ईवी खरीदने में सक्षम बनाना और स्थायी नौकरियाँ सुरक्षित करना भी है।"

पिछले 12 महीनों में, बीआईआई ने भारत के सबसे बड़े लास्ट-माइल लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं में से एक, लोडशेयर को अपनी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पेशकश का विस्तार करने के लिए नया वित्तपोषण प्रदान किया है।

इसने वाणिज्यिक ईवी निर्माता यूलर मोटर्स, छोटे व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए ईवी वितरण और वित्तपोषण मंच टर्नो और वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए बैटरी-स्वैपिंग नेटवर्क बैटरी स्मार्ट में भी निवेश किया है। बीआईआई 2027 तक 10,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क बनाने के लिए चार्जज़ोन का भी समर्थन कर रहा है।

2022 में बीआईआई ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ साझेदारी में एक नए यात्री इलेक्ट्रिक वाहन उद्यम के लिए $250 मिलियन तक की प्रतिबद्धता जताई।

बीआईआई की ईवी रणनीति भारत में जलवायु-शमन पहलों और हरित प्रौद्योगिकियों में नवाचार में $1 बिलियन तक निवेश करने की इसकी व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

चिकित्सा में आत्मनिर्भरता के कदम

विजय गर्ग

केंद्र सरकार ने पिछले एक दशक में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के साथ आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कई पहल की है। इन कोशिशों से दुनिया में भारत की साख बेहतर हुई है। चंद्रयान 3 3 की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने अब स्वास्थ्य क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों को नया 'काम' सौंपा है। इससे भारत चिकित्सा के क्षेत्र में छलांग लगाने में कामयाब हो सकता है। यह ऐसी योजना है, जो आजाद भारत में पहली बार एक चुनौती के के रूप में पूरी की जानी है। इस तरह की योजना को दुनिया में पहले कभी किसी देश ने नहीं लागू किया। यानी जिन बीमारियों का इलाज कोई नहीं ढूंढ पाया, उसे भारतीय वैज्ञानिक ढूंढेंगे। इसके लिए सरक ने विश्व में प्रथम चुनौती लक्ष्य भी तय किया है, जिसकी जिम्मेदारी नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र (आइसीएमआर) को सौंपी है। इससे दुनिया में चिकित्सा क्षेत्र में देश की साख एक नए भारत के रूप में बनेगी और यह यह अमेरिका, पेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस, जापान और जर्मनी के साथ आगे बढ़ सकेगा।

जिन विकसित देशों ने चिकित्सा क्षेत्र में नए और मौलिक शोध के जरिए आश्चर्यजनक परिणाम हासिल किए हैं, वहां के वैज्ञानिकों को सभी जरूरी सुविधाए दी गई भारत भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। हमारी जो वैज्ञानिक मेधा, धन, सुविधाएं और उदारीकरण के कारण विदेश चली जाती थी, वह अब भारत में रह कर अपनी विलक्षण प्रतिभा का लोहा मनवाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार शोधार्थी वैज्ञानिकों को सभी कुछ मुहैया करा रही है, जिससे चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हो सकें। सरकार की इस नई योजना को पूरा करने के लिए देश के चिकित्सा संस्थानों को मिल कर काम करना होगा। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार एक पत्र भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरे चंद्रयान 3 से प्रेरित होकर दुनिया में पहली बार चिकित्सा के क्षेत्र में भारत एक ऐसी पहल करने जा रहा है, जिससे उसके वैज्ञानिकों को नए और लीक से हट कर विचारों पर काम करने का 1 मौका मिलेगा। गौरतलब है कि देश में वैज्ञानिकों ने कोरोना के दौरान कोविड 19 के टीके तैयार करने अपनी पूरी शोध शक्ति लगा दी थी। केंद्र सरकार ने तीन तरह के टीके तैयार करवाए थे, जो दुनिया के अनेक देशों को सहयोग के रूप में भेजे गए थे। इससे भारत की दुनिया में प्रशंसा हुई। । केंद्र सरकार शोध के जरिए दवा खोजने और उपचार करने

के मद्देनजर आगे बढ़ रही वष्य में हो सकने वाली नई बीमारियों के उपचार के लिए शोध वास्ते केंद्र सरकार की तरफ से धन मुहैया कराया जा रहा है निश्चित है कि इससे चिकित्सा जगत में भारत विकसित देशों में शुमार होने की कतार में खड़ा हो सकेगा। यदि भविष्य में हो सकने वाली नई बीमारियों का बेहतर उपचार हमारे चिकित्सा वैज्ञानिकों ने खोज लिया, तो भारत दुनिया का महत्त्वपूर्ण चिकित्सा शोधार्थी के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। केंद्र सरकार ने आइसीएमआर के जरिए सबसे जटिल बीमारियों के उपचार के लिए वैज्ञानिकों को तैयार करने का निश्चय किया है। इससे वे जटिल बीमारियों का उपचार करने के लिए प्रेरित होंगे। इस पहल का उद्देश्य लीक से हट कर भविष्य की तैयारियों, नए ज्ञान सृजन और खोज को बढ़ावा देना है। इससे बेहतर औषधियां और नए टीके मिलेंगे। लोगों का आसानी से उपचार हो सकेगा। आइसीएमआर के मुताबिक, अगले कुछ सप्ताह में सभी प्रस्तावों को एकत्रित करने के बाद समिति इनका मूल्यांकन करेगी और उसके बाद अंतिम प्रस्तावों पर शोध होंगे, जिन्हें अधिकतम तीन साल में पूरा करना होगा। इस पहल में सभी सरकारी मेडिकल कालेज, देश के सभी शीर्ष चिकित्सा संस्थानों के साथ दिल्ली सहित सभी एम्स, आइसीएमआर के सभी संस्थानों के अलावा यूजीसी, एआइसीटीई और एनएमसी में पंजीकृत संस्थानों के शोधकर्ता शामिल हो सकते हैं। इस लिहाज से देखें तो देश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थानों और शिक्षा संस्थाओं एवं संगठनों के जरिए आजादी के बाद चिकित्सा क्षेत्र में गंभीर पहल की गई है। चिकित्सा के क्षेत्र में भारत प्रत्येक नागरिक को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में अभी बहुत पीछे है। ऐसे में लाइलाज, असंभव लगने वाली बीमारियों का इलाज करने के मद्देनजर केंद्र सरकार की यह यह पहल स्वागतयोग्य है। । मगर सवाल है कि क्या सरकार कैंसर, पक्षाघात, मधुमेह, हृदयघात और अस्थमा जैसी बीमारियों का बेहतर इलाज, खासकर गांवों में आम आदमी को, उपलब्ध करा पाई है।

केंद्र की नीतियां इस वक्त बेहतर योजनाओं के जरिए सबको समुचित सहूलियतें। मुहैया कराने 1 की है। है। इनका। उद्देश्य हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाते हुए कामयाबी की उन बुलंदियों को हासिल करना है, जो विकासशील देशों के देशों के लिए करीब नामुमकिन माना जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में नए शोध कराने और बेहतर परिणाम हासिल कर उसे मानवता के उपयोग के लिए देने की नीति निश्चय ही भारत की सर्वजन हिताय वाली नीति का ही हिस्सा है। भारत में सात दुर्लभ रोगों में से महज पांच फीसद बीमारियों का इलाज ही ही संभव है। अभी देश में देश में हालत यह है कि बीस में से एक व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित है और उसका उपचार समुचित तरीके से नहीं हो पा रहा है। आइसीएमआर के मुताबिक, देश में सात करोड़ और दुनिया में 35 में 35 करोड़ लोग दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त हैं।

भारत में ऐसी अनेक बीमारियों से लोग पीड़ित हैं, जिनके लक्षण देख कर डाक्टर समझ पाते कि यह बीमारी' है क्या ! मिसाल के तौर पर 'एसेंथामोएबा केराटाइटिस' 'ऐसी बीमारी है जिससे आदमी अंधा हो जाता है। इसका समुचित इलाज भारत में उपलब्ध नहीं है। । इसी तरह 'क्रुत्जफेल्ट-जैकब' ऐसी लाइलाज बीमारी है, जिसकी वजह से घातक मस्तिष्क घात हो जाया लक्षण के आधार पर समुचित तरह हजारों बीमारियां हैं, जिनके लिए सस्ता, सहज और कारगर इलाज खोजने की जरूरत है। केंद्र सरकार को चाहिए कि लाइलाज बीमारियों और दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए सबसे पहले गौर करे, जिस पर अभी शोध की बहुत जरूरत है। वर्तमान में केंद्रीय तकनीकी समिति (सीटीसीआरडी) की सिफारिश पर असाध्य रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति के तहत 63 रोगों को ही शामिल किया गया है। इसमें प्रति रोगी 50 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। भारत में चिकित्सा उपचार केंद्रों की संख्या जरूरत से बहुत कम कम है। गांवों में तो स्थिति और खराब है। इसलिए इस तरफ समुचित ध्यान जरूरत है। इसी तरह आबादी के मुताबिक चिकित्सकों की संख्या बहुत कम है। गांवों में एक लाख आबादी पर एक डाक्टर ही उपलब्ध है। । इसलिए अब भविष्य में होने वाली बीमारियों के नए उपचार की खोज करनी होगी। वहीं, वर्तमान में लाइलाज, दुर्लभ और अति गंभीर बीमारियों के सहज और सबको समुचित उपचार उपलब्ध कराने पर भी सोचने की जरूरत है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर

समान शिक्षा के उत्प्रेरक के रूप में एक राष्ट्र एक सदस्यता

विजय गर्ग

गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, खासकर भारत के दूरदराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण संसाधन सामग्री तक पहुंच छात्रों और अनुसंधान विद्वानों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, खासकर भारत के दूरदराज के इलाकों में। जबकि डिजिटल युग ने सूचना प्रसारित करने के तरीके को बदल दिया है, भौतिक पुस्तकालय अकादमिक उत्कृष्टता की आधारशिला बने हुए हैं। फिर भी, ये आवश्यक ज्ञान केंद्र तेजी से अतीत के अवशेष बनते जा रहे हैं, जो केवल राष्ट्रीय संस्थानों और चयनित विश्वविद्यालयों से जुड़े कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए ही सुलभ हैं। अब तक, देश की प्रत्येक एजेंसी ने अपने डिजिटल लाइब्रेरी संसाधनों के लिए सदस्यता ले ली है, यूजीसी के पास इनफ्लिबनेट है, जो चयनित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उपलब्ध है, सीएसआईआर और डीएसटी संस्थानों के पास राष्ट्रीय ज्ञान संसाधन कंसोर्टियम (एनकेआरसी) है; आईसीएआर संस्थानों को सीईआरए आदि करोड़ों रुपये का भुगतान करना पड़ता है। कई मामलों में, ये ई-संसाधन केवल मेजबान संस्थान के उपयोगकर्ताओं तक ही सीमित हैं, हालांकि इन्हें सार्वजनिक धन के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। यदि महत्वाकांक्षी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो इस असमानता को दूर करने और शैक्षिक परिदृश्य को पुनर्जीवित करने की क्षमता है। तकनीकी प्रगति के बावजूद, भारत में अब तक गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण नहीं किया जा सका है। अधिकांश कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों को विभिन्न कारणों से चिंताजनक गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। पुस्तकालयों में जाने के प्रति युवा पीढ़ी की रुचि की कमी और घटती निधि ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। दुर्भाग्य से, कई सार्वजनिक संस्थानों में, मुख्य रूप से राष्ट्रीय संस्थानों से जुड़े पुस्तकालयों में, पुस्तकालय कर्मचारियों में अक्सर पाठकों के लिए स्वागत योग्य वातावरण बनाने के लिए उत्साह और पारस्परिक कौशल का अभाव होता है। यह, बदले में, सबसे वास्तविक पाठकों को भी अलग-थलग कर देता है, जो बाधाओं के बावजूद, पुस्तकालयों में जाने का प्रयास करते हैं। समर्थन की कमी और एक अनामंत्रित माहौल छात्रों और शोधकर्ताओं को शैक्षणिक और बौद्धिक गतिविधियों के लिए पुस्तकालयों को अपना पसंदीदा स्थान बनाने से रोक सकता है, जिससे पुस्तकालय संस्कृति और भी नष्ट हो रही है जो पहले से ही खतरे में है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल का उद्देश्य एक केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रव्यापी उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करके इन चुनौतियों का समाधान करना है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्रिकाओं, डेटाबेस और ई-पुस्तकों के लिए थोक सदस्यता पर बातचीत करके, पहल यह सुनिश्चित कर सकती है कि भौगोलिक या आर्थिक बाधाओं की परवाह किए बिना प्रत्येक छात्र के पास समान ज्ञान है। एक राष्ट्रीय संस्थान में एक छात्र या विद्वान को जो मिलता है वह देश के सुदूर कोने में स्थित विश्वविद्यालय में एक छात्र को मिलेगा। यह ज्ञान संसाधन का

लोकतंत्रीकरण कर रहा है। हालाँकि, इस पहल की सफलता केवल पहुंच से कहीं अधिक पर निर्भर करती है। भारत को अपने पुस्तकालय पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए एक समानांतर प्रयास की आवश्यकता है। डिजिटल युग में भी, भौतिक पुस्तकालय प्रतिबिंब और सहयोग के स्थान के रूप में अपूरणीय हैं। सरकार को पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराना चाहिए और कुशल, प्रेरित पुस्तकालयाध्यक्षों की भर्ती के लिए भी कदम उठाना चाहिए जो पाठकों की बढ़ती जरूरतों को समझते हैं और प्रभावी ढंग से डिजिटल और भौतिक संसाधनों का प्रबंधन कर सकते हैं। समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को प्रत्येक पंजीकृत छात्र और विद्वान को व्यक्तिगत लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान करना होगा, जिससे किसी भी समय, कहीं भी संसाधनों तक सीधी पहुंच सक्षम हो सके। यह पारंपरिक संस्थागत को दरकिनार कर देगागेटकीपिंग और अधिक पाठक-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना। नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यान्वयन की कमी या पूरक उपायों की उपेक्षा के कारण यह महत्वाकांक्षी योजना विफल न हो। ज्ञान प्रगति की आधारशिला है और इस तक पहुंच को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, न कि विशेषाधिकार के रूप में। इस पहल की क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए, यह आवश्यक है कि सरकार प्रत्येक छात्र के लिए इन संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करे।

तकनीक बनाम इंसानियत

विजय गर्ग

आज की दुनिया एक बड़े परिवर्तन के दौर गुजर रही है। डिजिटल तकनीक के व्यापक प्रसार ने हमारी दिनचर्या और सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमता और सोशल मीडिया ने न केवल हमें एक नए युग में प्रवेश कराया है, बल्कि हमारी इंसानियत पर भी सवाल खड़े किए हैं। आज जब अपने चारों ओर की दुनिया को देखा जाए तो कोई भी संवेदनशील व्यक्ति यह सोचने पर मजबूर हो सकता है कि क्या यह तकनीकी क्रांति हमें वास्तव में जोड़ कर रख रही है या हमें और भी अलग-थलग कर रही है ! एक श्लोक है- 'असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय ।' यानी हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। यह श्लोक इस बात की याद दिलाता है कि सच्चा मार्ग वही है, जो अंधकार और असत्य से मुक्त हो। इसी तरह, आज हमें तकनीक के उजाले में खोते हुए उन मूल्यों को याद रखना होगा, जो हमें मानवता की ओर ले जाते हैं ।

तकनीक ने भले ही हमें वैश्विक स्तर पर जुड़ने का अवसर दिया हो, लेकिन वास्तविकता में हमने अपनी आसपास की दुनिया से दूरी बना ली है। आभासी दुनिया में जुड़ने के सुख की हकीकत यह है कि सोशल मीडिया पर हजारों लोग दोस्ती की सूची में हो सकते हैं, उन्हें हमारा लिखा हुआ या कोई और सामग्री पसंद आती है, मगर वास्तव में कोई हमसे जुड़ा नहीं होता। हमारा पड़ोसी तक हमारे दुख शामिल नहीं होना चाहता। ज्यादातर लोग एक ही घर में रह कर अपने स्मार्टफोन में डूबे रहते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि इस डिजिटल दुनिया में हम और भी अकेले होते जा रहे हैं। उन दिनों को याद किया जा सकता है, जब में परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर हम वास्तविक बातचीत किया करते थे। आज वह आपसी संवाद एक 'कमेंट' या 'इमोजी' तक सीमित हो गया है।

खुद में सिमटने के उदाहरण अपने आसपास हर जगह देखे जा सकते हैं। किसी व्यावसायिक माल में जमा लोगों को देख कर उनके भी संवेदनशील होने के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ समय पहले एक बुजुर्ग एक जगह असहाय बैठे थे। शायद उन्हें मदद की जरूरत थी। चारों ओर से लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सभी अपने-अपने स्मार्टफोन या बाजार से खरीदारी में व्यस्त । एक व्यक्ति ने जब उनसे बात की, तब पता चला कि उन्हें अपने बेटे से संपर्क करने में परेशानी हो रही थी । उस व्यक्ति ने उनकी मदद की, तब उनकी आंखों में राहत और आभार का भाव उभरे। तकनीक ने हमें भले ही एक नई दुनिया दी हो, लेकिन हम अपनी इंसानियत और आपसी जुड़ाव से कहीं दूर हो गए यह विडंबना है कि जब हमारे पास इतनी तकनीकी प्रगति है, तो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी उसी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं। तनाव, अवसाद और अकेलापन जैसे मुद्दे अब आम हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल युग में इन समस्याओं की वृद्धि इस बात का संकेत है कि हम अपने वास्तविक मानवीय रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। अब वह समय नहीं रहा जब हम अपनों के साथ समय बिताने से आत्मिक शांति पाते थे । एक दौर था जब इंसानियत, प्यार और देखभाल हमारे रिश्तों की नींव हुआ करती थी । अब यह सब डिजिटल संकेत और स्क्रीन पर उभरते 'नोटिफिकेशन' या सूचनाओं और संदेशों में बंधकर रह गया है।

'विज्ञान ने संसार को एक बहुत बड़ी चीज दी है- तथ्यों को पहचानने की शक्ति । लेकिन प्रेम ही वह तत्त्व है, जो मानव हृदय को सही दिशा देता है।' प्रेमचंद की ये पंक्तियां हमें इस बात का अहसास कराती हैं कि तकनीक और विज्ञान कितनी भी उन्नति कर लें, आखिरकार मानवीय संवेदनाएं ही हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं और जीवन को सार्थक बनाती हैं। इस बात को लेकर चिंतित होना चाहिए कि क्या हम वाकई सही दिशा में जा रहे हैं। हालत यह हो गई है कि कोई हादसा हो जाता है, कोई अपराध हो रहा होता है, उस समय भी कुछ लोग मदद पहुंचाने या उसके लिए दौड़ पड़ने के बजाय अपने स्मार्टफोन निकाल कर झट से वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं । सवाल है कि क्या तकनीक हमारी संवेदनाओं और सोचने-समझने की दिशा को भी प्रभावित कर रही है।

तकनीकी प्रगति ने जीवन को सरल बना दिया है, लेकिन इसने हमारे दिलों को जटिल भी कर दिया है। क्या हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं, जहां इंसानियत और मानवीय संवेदनाओं को तकनीक से परे एक नया आयाम देना होगा ? इस प्रश्न का उत्तर हम सभी को मिलकर खोजना होगा। तकनीक का सही उपयोग तभी संभव है, जब यह हमारे मानवीय मूल्यों को संजोए रखे। तकनीकी के उपयोग का उद्देश्य हमारी जिंदगी को आसान बनाना था, लेकिन कहीं न कहीं यह हमें आपस में जोड़ने के बजाय भावनात्मक रूप से दूर कर रही है । हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तकनीक का प्रयोग इंसानियत को मजबूत करने के लिए हो, न कि इसे कमजोर करने के लिए ।

क्यों किताबें पढ़ना आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए

विजय गर्ग

1. ज्ञान का राजमार्गः किताबें लगभग किसी भी विषय पर ज्ञान का एक विशाल भंडार प्रदान करती हैं। इतिहास, विज्ञान, दर्शन में गहराई से गोता लगाएँ या नए शौक और रुचियों का पता लगाएँ।

2. बढ़ी हुई शब्दावलीः नियमित रूप से पढ़ने से आपको शब्दावली की एक विस्तृत श्रृंखला का पता चलता है, जिससे आपके संचार कौशल और समझ में सुधार होता है।

3. याददाश्त बढ़ाता हैः अध्ययनों से पता चलता है कि पढ़ना आपकी याददाश्त और संज्ञानात्मक कार्य को तेज करने में मदद कर सकता है, जिससे आपका दिमाग सक्रिय और व्यस्त रहता है।

4. तनाव में कमीः एक अच्छी किताब के साथ आराम करना मानसिक पलायन का एक रूप हो सकता है, जो दैनिक चिंताओं से अस्थायी राहत और आराम करने का मौका देता है।

5. बेहतर फोकस और एकाग्रताः आज की तेज़-तर्रार दुनिया में जो विकर्षणों से भरी हुई है, पढ़ना आपकी ध्यान केंद्रित करने और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को मजबूत करता है।

6. सहानुभूति और परिप्रेक्ष्यः काल्पनिक पात्रों के जूते में कदम रखने से आपको सहानुभूति विकसित करने और विभिन्न दृष्टिकोणों की गहरी समझ हासिल करने की अनुमति मिलती है।

7. रचनात्मकता में वृद्धिः पढ़ने से आपको नए विचार और विचार प्रक्रियाएँ मिलती हैं, जो संभावित रूप से आपकी खुद की रचनात्मकता और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा देती हैं।

8. मजबूत लेखन कौशलः अच्छी तरह से लिखे गए गद्य में खुद को डुबोने से आपकी लेखन शैली, वाक्य संरचना और समग्र संचार स्पष्टता में सुधार हो सकता है।

9. बेहतर नींद की गुणवत्ताः सोने से पहले स्क्रीन टाइम की जगह किताब पढ़ें। पढ़ने की शांत प्रकृति आपको आराम करने और तनावमुक्त होने में मदद कर सकती है, जिससे बेहतर नींद की गुणवत्ता को बढ़ावा मिलता है।

कहानी !! अनोखा दोस्त कौआ !!

विजय गर्ग

एक कौआ था। वह एक किसान के घर के आँगन के पेड़ पर रहता था। किसान रोज़ सुबह उसे खाने के लिए पहले कुछ देकर बाद में खुद खाता था। किसान खेत में चले जाने के बाद कौआ रोज़ उड़ते-उड़ते ब्रह्माजी के दरबार तक पहुँचता था और दरबार के बाहर जो नीम का पेड़ था, उस पर बैठकर ब्रह्माजी की सारी बातें सुना करता था। शाम होते ही कौआ उड़ता हुआ किसान के पास पहुँचता और ब्रह्माजी के दरबार की सारी बातें उसे सुनाया करता था।

एक दिन कौए ने सुना कि ब्रह्माजी कह रहे हैं कि इस साल बारिश नहीं होगी। अकाल पड़ जायेगा। उसके बाद ब्रह्माजी ने कहा - ₹पर पहाड़ो में खूब बारिश होगी।₹

शाम होते ही कौआ किसान के पास आया और उससे कहा - ₹बारिश नहीं होगी, अभी से सोचो क्या किया जायेे₹।

किसान ने खूब चिन्तित होकर कहा - ₹तुम ही बताओ दोस्त क्या किया जायेे₹।

कौए ने कहा - ₹ब्रह्माजी ने कहा था पहाड़ों में जरुर बारिश होगी। क्यों न तुम पहाड़ पर खेती की तैयारी करना शुरु करो ?₹

किसान ने उसी वक्त पहाड़ पर खेती की तैयारी की। आस-पास के लोग जब उस पर हँसने लगे, उसे बेवकूफ कहने लगे, उसने कहा - ₹तुम सब भी यही करो। कौआ मेरा दोस्त है, वह मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाता हैे₹ - पर लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। उस पर और ज्यादा हँसने लगे।

उस साल बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा। वह किसान ही अकेला किसान था जिसके पास ढेर सारा अनाज इकट्ठा हो गया। देखते ही देखते साल बीत गया इस बार कौए ने कहा - ₹ब्रह्माजी का कहना था कि इस साल बारिश होगी। खूब फसल होगी। पर फसल के साथ-साथ ढेर सारे कीड़े पैदा होगें। और कीड़े सारी फसल के चौपट कर देंगे।₹

इस बार कौए ने किसान से कहा - ₹इस बार पहले से ही तुम मैना पंछी और छछूंदों को ले आना ताकि वे कीड़ों को खा जाये।₹

किसान ने जब ढेर सारे छछूंदों को ले आया, मैना और पंछी को ले आया, आसपास के लोग उसे ध्यान से देखने लगे - पर इस बार वे किसान पर हंसे नहीं।

इस साल भी किसान ने अपने घर में ढेर सारा अनाज इकट्ठा किया।

इसके बाद कौआ फिर से ब्रह्माजी के दरबार के बाहर नीम के पेड़ पर बैठा हुआ था जब ब्रह्माजी कर रहे थे - ₹फसल खूब होगी पर ढेर सारे चूहे फसल पर टूट पड़ेगे।₹

कौए ने किसान से कहा - ₹इस बार तुम्हें बिल्लियों को न्योता देना पड़ेगा - एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारी बिल्लियाँ₹।

इस बार आस-पास के लोग भी बिल्लियों को ले आये।

इसी तरह पूरे गाँव में ढेर सारा अनाज इकट्ठा हो गया।

कौए ने सबकी जान बचाई।

एक्सिस बैंक ने महिलाओं के लॉन्च किया खास बचत खाता, मिलेंगे कई हेल्थ और फाइनेंशियल फायदे

परिवहन विशेष न्यूज

नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (एनएसओ) के हालिया डेटा के अनुसार भारत के कुल बैंक जमा में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 20.8 फीसदी है। वहीं सभी बैंक खाताधारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी 36.4 फीसदी है। महानगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की जमा राशि केवल 16.5 फीसदी है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 30 फीसदी है। एक्सिस बैंक का दावा है कि उसका ARISE Women's Savings Account महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगा।

नई दिल्ली। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े में से एक एक्सिस बैंक ने 'ARISE Women's Savings Account' लॉन्च किया है। इसका मकसद महिलाओं की वित्तीय जरूरत पूरा करने के साथ उन्हें जरूरी हेल्थ बेनेफिट देना है। इस बचत खाते की सुविधाओं की बात करें, तो इसमें डेडिकेटेड महिला वित्तीय विशेषज्ञ, स्टॉक की कस्टमाइज्ड बास्केट और उनके स्वास्थ्य, जीवनशैली और परिवार की मदद करने जैसे फायदे शामिल हैं।

एक्सिस बैंक ने महिलाओं के लिए क्यों शुरू किया बचत खाता

नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (एनएसओ) के हालिया डेटा के अनुसार, भारत के कुल बैंक जमा में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 20.8 फीसदी है। वहीं, सभी बैंक खाताधारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी 36.4 फीसदी है। महानगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की जमा राशि केवल 16.5 फीसदी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 30 फीसदी है। इससे पता चलता है कि वित्तीय असमानता को दूर करने और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। एक्सिस बैंक का दावा है कि उसका ARISE Women's Savings Account इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी ने कहा, ''मौजूदा वित्तीय परिदृश्य में अब सभी के लिए एक ही उपाय नहीं हो सकता। अब समय आ गया है कि महिलाओं के सामने आने वाली खास चुनौतियों और अवसरों पर फोकस किया जाए। एराइज बचत खाता महिलाओं को उनकी शक्ति और क्षमता तक पहुंचने में काफी मदद करेगा। हमारा मानना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने से एक लहर जैसा प्रभाव पैदा होता है। इससे परिवार, समुदाय और पूरे देश को मबूती मिलती है।''

पारिवारिक बैंकिंग कार्यक्रम- तीन पारिवारिक सदस्यों को विस्तारित लाभ। इसमें शुरुआती रकम के बिना भी बच्चों के खातों को जोड़ने का विकल्प शामिल है।

लॉकर लाभ- छोटे और मध्यम लॉकरों पर पहले साल के लिए कोई किराया नहीं। दूसरे साल से सामान्य रेट के मुकाबले 50 फीसदी की छूट मिलेगी।

एराइज डेबिट कार्ड- पीओएस पर 5 लाख रुपये और एटीएम पर 1 लाख रुपये के साथ हाई ट्रांजैक्शन लिमिट। लाउंज एक्सेस और रिवॉर्ड प्वाइंट भी शामिल।

कॉम्प्लीमेंट्री नियो क्रेडिट कार्ड- बुकमायशो पर तत्काल 10 फीसदीछूट (100 रुपये/माह तक), जोमैटो ऑर्डर पर 40 प्रतिशत तक की छूट और हर 200 रुपये खर्च पर 1 एज रिवार्ड पॉइंट शामिल।

ARISE Women's Savings Account के वित्तीय फायदे

महिला विशेषज्ञों द्वारा वित्तीय मार्गदर्शन।

डीमैट खाते के लिए पहले साल में (एएमसी) से छूट।

स्टॉक की एक कस्टमाइज्ड बास्केट में निवेश का विकल्प।

स्मार्टएज पर 50 प्रतिशत छूट के साथ स्टॉक की सिफारिश

स्वास्थ्य सेवा लाभ

पेप स्मियर, मैमोग्राम और कैंसर स्क्रीनिंग सहित महिलाओं के लिए विशेष डायग्नोस्टिक परीक्षणों पर 70 प्रतिशत तक की छूट।

सामान्य चिकित्सकों, पोषण विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों और बाल रोग विशेषज्ञों सहित शीर्ष अस्पताल विशेषज्ञों के साथ असीमित परामर्श।

फार्मेसी नुस्खों पर 10 फीसदी तक की छूट, त्वचा विशेषज्ञों के साथ असीमित ऑन-कॉल परामर्श सहित वेलनेस सत्रों तक पहुंच।

लाइफस्टाइल ऑफर और छूट

फर्स्टक्राई क्लब सदस्यता के साथ विशेष चाइल्डकेयर लाभ।

निःशुल्क स्विगी वन मेंबरशिप।

नाइका पर सौंदर्य और फैशन उत्पादों पर 10 प्रतिशत की छूट।

एमपीसी की बैठक हुई शुरू, कल होगा फैसलों का एलान

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय रिजर्व बैंक की (Reserve Bank Of India) की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (RBI MPC Meet 2024) बैठक कल से शुरू हो गई है। इस बैठक में लिए गए फैसलों का एलान शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर करेंगे। लोनधारकों की नजर रेपो रेट पर बनी हुई है। अगर रेपो रेट में कटौती होती है तो लोन की ईएमआई कम हो जाएगी।

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक की (Reserve Bank Of India) की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (RBI MPC Meet 2024) बैठक शुरू हो गई है। यह बैठक तीन दिवसीय होती है। इस बैठक में रेपो रेट (Repo Rate) समेत कई फैसले लिए जाते हैं।

आपको बता दें कि रेपो रेट का सीधा कनेक्शन लोन की ईएमआई (EMI) पर होता है। अगर रेपो रेट में कटौती होती है तो लोन की ईएमआई कम हो जाती है। वहीं रेपो रेट में बढ़ जाने पर ईएमआई भी बढ़ जाती है। आरबीआई की एमपीसी बैठक हर दो महीने में होती है। वैसे तो यह 2024 की आखिरी बैठक है, लेकिन वित्तीय वर्ष के हिसाब से आखिरी बैठक फरवरी में होगी।

एमपीसी बैठक क्यों जरूरी

आरबीआई की एमपीसी बैठक में मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कई फैसले लिए जाते हैं। वैसे तो मनी फ्लो के लिए रेपो रेट को जरूरत के हिसाब से घटाया या बढ़ाया जाता है। इसके अलावा महंगाई को भी कम करने के लिए रेपो रेट (Repo Rate) में बदलाव किया जाता है।

मार्केट में जब भी कोई चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो सप्लाई को भी बैलेंस करने की जरूरत होती है। अगर वह बैलेंस न हो तो फिर चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। ऐसे में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई समय-समय पर बैठक करती है। इस बैठक की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर करते हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikant Das) हैं।

एमपीसी बैठक में लिए गए फैसलों का एलान तीसरे दिन होते हैं। इस बार यह बैठक 4 दिसंबर से शुरू हुई थी। अब बैठक का फैसला कल यानी 6 दिसंबर 2024 को आएगा। फैसलों की घोषणा खुद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास करेंगे।

नियमों के अनुसार एक वित्त वर्ष में 4 एमपीसी बैठक होनी चाहिए। अगर किसी वर्ष में 4 बैठक से कम बैठक होती है तो इसके लिए आरबीआई को नोटिफिकेशन जारी करना होता है। इस नोटिफिकेशन में केंद्र बैंक को बैठक की तारीख की जानकारी देनी होती है।

क्यों अहम है रेपो रेट

रेपो रेट एक तरह का ब्याज दर होता है। केंद्र बैंक देश के सभी बैंक को इसी दर पर कर्ज देता है। ऐसे में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मनी फ्लो को कम करने के लिए रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है। वहीं महंगाई को कम करने के लिए रेपो रेट में कटौती की जाती है ताकि मनी फ्लो ज्यादा हो पाए।

बैन हटा तो शेयर ने पकड़ी रफ्तार, अनिल अंबानी के साथ निवेशक को हुआ लाभ

अनिल अंबानी की पावर कंपनी रिलायंस पावर एक बार फिर से फोकस में आ गए हैं। दरअसल दो सत्रों से कंपनी के शेयर में अपर सर्किट लग रहा है। आज भी रिलायंस पावर के शेयरों में अपर सर्किट लगा है। SECI के बैन हटाने के बाद अनिल अंबानी की कंपनी के शेयर में तेजी आई है। पढ़ें पूरी खबर...

नई दिल्ली। पिछले दो सत्रों से अनिल अंबानी की पावर कंपनी रिलायंस पावर के शेयरों में तेजी देखने को मिली। यह तेजी कंपनी पर लगाए गए बैन के हटने के बाद आई है।

कौन-सा बैन हटा?

नवंबर में Solar Energy Of India (SECI) ने रिलायंल पावर पर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप के तहत 3 साल के लिए ट्रेडर बोली लगाने पर रोक लगा दी थी। दरअसल, SECI ने अपने बयान में कहा था कि महाराष्ट्र एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड (Reliance NU Bess Ltd) के प्रोजेक्ट के लिए जो बैंक गारंटी जमा की गई थी, वह फर्जी थी। इस वजह से कंपनी पर बैन लगा दे।

बैन लगने के बाद रिलायंस पावर ने अदालत का दरवाजा खड़खड़ाया और SECI की कार्रवाई को चुनौती दी। कंपनी ने कहा कि वह खुद धोखाधड़ी जालसाजी के शिकार हुए थे। अदालत के फैसले के बाद SECI ने रिलायंस पावर पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस ले लिया।

शेयर ने पकड़ी रफ्तार

रिलांयस पावर पर लगे बैन हटने के बाद बीते कारोबारी सत्र में कंपनी के शेयर (Reliance Power Share) में अपर सर्किट लगा। आज भी कंपनी के शेयर में अपर सर्किट लगा है। बुधवार को कंपनी के शेयर 41.09 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ था। 4 अक्तूबर 2024 को कंपनी के शेयर ने 53.72 रुपये का 52-वीक हाई टच किया था। इसके बाद से कंपनी के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली और यह 33 रुपये प्रति शेयर के भाव पर आ गया। हालांकि, अब शेयर ने अपने लो लेवल से एकहद तक रिकवर हो गया है।

अगर शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो बीते एक साल में रिलायंस पावर के शेयर ने 93.45 फीसदी का रिटर्न दिया है। आज कंपनी के शेयर 43.14 रुपये प्रति शेयर (Reliance Power Share Price) पर पहुंच गया है।

शेयर बाजार की चाल

आज सुबह आईटी शेयरों में खरीदारी ने बाजार को बढ़त हासिल करने में मदद किया है। हालांकि, बाद में बाजार में गिरावट आई। 12 बजे सेंसेक्स 0.22 फीसदी की गिरावट के साथ 80,775.64 अंक और निफ्टी 0.35 फीसदी गिरकर 24,382.75 अंक पर कारोबार कर रहा है।

सोना हुआ महंगा, चांदी भी चमकी; चेक करें लेटेस्ट प्राइस

परिवहन विशेष न्यूज

कारोबारियों ने कहा कि स्थानीय बाजारों में आभूषण विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं की ताजा मांग के कारण सोने में तेजी आई। चांदी की कीमत लगातार तीसरे दिन भी चमकी और गुरुवार को 1300 रुपये चढ़कर 93800 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। लगातार वैश्विक जोखिम साथ ही फ्रांस और दक्षिण कोरिया में राजनीतिक अनिश्चितता से सोने की कीमतों में उछाल आया है।

नई दिल्ली। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, जौहरियों और स्टॉकिस्टों की ताजा खरीदारी के कारण गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 79,000 रुपये के स्तर पर पहुंच गई। तीन दिन की गिरावट के बाद 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाली इस बहुमूल्य धातु की कीमत बुधवार को 300 रुपये बढ़कर 79,150 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि पिछले दिन इसका भाव 78,850 रुपये प्रति 10 ग्राम था।

कारोबारियों ने कहा कि स्थानीय बाजारों में आभूषण विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं की ताजा मांग के कारण सोने में तेजी आई। चांदी की कीमत लगातार तीसरे दिन भी चमकी और गुरुवार को 1,300 रुपये चढ़कर 93,800 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। बुधवार को यह 92,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

इस बीच, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर वायदा कारोबार में फरवरी डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध 160 रुपये या 0.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,932 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहे थे।

सोने की कीमतों पर क्या है एक्सपर्ट की राय

एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी रिसर्च एनालिस्ट (कमोडिटी एंड करेंसी) जतिन त्रिवेदी ने कहा, ₹सोने में स्थिरता रही। एमसीएक्स में सोने के 76,700-77,400 रुपये के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है। लगातार वैश्विक जोखिम, साथ ही फ्रांस और दक्षिण कोरिया में राजनीतिक अनिश्चितता से सोने की कीमतों में उछाल आया है।"

एक्सचेंज पर मार्च डिलीवरी वाले चांदी के अनुबंध 188 रुपये या 0.2 प्रतिशत की गिरावट के साथ 93,105 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गए। वैश्विक स्तर पर कॉमेक्स सोना वायदा 7.20 डॉलर या 0.27 प्रतिशत गिरकर 2,669 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, ₹व्यापारी गुरुवार को जारी होने वाले नए बेरोजगारी दावों और व्यापार संतुलन सहित अमेरिकी मैक्रोइकॉनोमिक डेटा का इंतजार करेंगे।"

कमोडिटी बाजार के विशेषज्ञों के अनुसार, बुलियन थोड़ा कमजोर रहा क्योंकि फेडरल रिजर्व (फेड) के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है, उन्होंने कहा कि सितंबर की नीति दर में कटौती श्रम बाजार का समर्थन करने का संदेश था।

पॉवेल ने कहा कि प्रगति दिखाने के बावजूद, मुद्रास्फीति पर जीत की घोषणा करना जल्दबाजी होगी। इस स्थिति में अमेरिकी केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति निर्धारित करने में सतर्क हो सकता है। अबान्स होल्डिंग्स के सीईओ चिंतन मेहता ने कहा, ₹व्यापारियों का माननाहै कि सोने की कीमतों में और वृद्धि होने की संभावना है, हालांकि अतिरिक्त ब्याज दर में कटौती में संभावित देरी से अल्पकालिक गिरावट हो सकती है। इससे कम कीमत पर खरीदारी का मौका मिलेगा।"

जॉब चेंज के साथ क्या UAN भी बदल जाता है, क्या कहता है ईपीएफओ का नियम

परिवहन विशेष न्यूज

बैंक और नियामक एजेंसियों के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि सब कुछ हो जाने के बावजूद जालसाजी के शिकार हुए व्यक्ति को पैसा लौटाने की प्रक्रिया अभी मुश्किल है। इसे आने वाले दिनों में आसान बनाने की कोशिश हो रही है। आरबीआई के स्तर पर काम चल रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसी प्रौद्योगिकी का सहारा लेने पर भी विचार हो रहा है।

नई दिल्ली। चंडीगढ़ की अंजलि चोपड़ा साइबर क्राइम की शिकार हुईं। जैसे ही उनके खाते से 80 हजार रुपये कटे, उन्हें इस बात का आभास हो गया कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। बैंक को फोन किया। साइबर अपराध वाले हेल्पलाइन नंबर को भी जानकारी दी। पुलिस के पास भी गईं और एफआईआर करवाई। इस सबके बावजूद उनके खाते में पैसा आने में दो महीने का वक्त लग गया।

लेकिन अंजलि चोपड़ा खुशकिस्मत हैं कि उनकी मेहनत की कमाई मिल गई। साइबर जालसाजी के शिकार होने वाले दूसरे हजारों लोगों की किस्मत वैसी नहीं होती। एफआईआर करवाने के बावजूद और पुलिस जांच में सत्यता प्रमाणित होने के बावजूद फ्रॉड करने वाले खातों से पैसा वापस लेना अभी भी टेढ़ी खीर है।

बैंकों व नियामक एजेंसियों के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि सब कुछ हो जाने के बावजूद जालसाजी के शिकार हुए व्यक्ति को पैसा लौटाने की प्रक्रिया अभी दुरूह है और आने वाले दिनों में इसे आसान बनाने की कोशिश हो रही है। आरबीआई के स्तर पर काम चल रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसी प्रौद्योगिकी का सहारा लेने पर भी विचार चल रहा है।

बैंकिंग सिस्टम में तालमेल की कमी से दिक्कत

गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर (आइ4सी) ने पिछले दिनों अपनी एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी है जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि कैसे बैंकिंग सिस्टम के बीच बेहतर सामंजस्य नहीं होना साइबर क्राइम करने वालों को मदद कर रहा है।

देश के बैंकिंग सिस्टम की सबसे बड़ी असफलता यह है कि फर्जी प्रपत्रों के आधार पर खाता खोलने पर रोक नहीं लग पाई है। पिछले साल साइबर अपराध से जुड़े 4.5 लाख बैंक खातों को जब्त किया गया है। ये बैंक खाते साइबर अपराध करने वालों ने लोगों से लूटी गई राशि को ट्रांसफर करने में इस्तेमाल किया है।

आई4सी ने यह भी जानकारी दी है कि इन बैंक खातों में 17 हजार करोड़ रुपये की राशि जमा की गई है। यह शक भी जताया गया है कि फर्जी कागजों पर खोले गये इन खातों के पीछे बैंकों के कर्मचारी या बैंक प्रबंधकों की भी संलिप्तता हो सकती है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने जुलाई, 2024 में कहा था कि कुछ बैंकों के पास लाखों खातों में लंबे समय से कोई लेन-देन नहीं हुआ है। इनमें से कुछ खाताओं का इस्तेमाल फ्रॉड के लिए हो रहा है।

10 प्रतिशत से ज्यादा पैसा नहीं लौट पाता

बैंकिंग क्षेत्र के जानकार बताते हैं कि वित्तीय फ्रॉड से जो राशि बैंक खाते से निकल जाती है उसकी वापसी का औसत 10 फीसद से ज्यादा का नहीं है। फ्रॉड करने वाले पहले से ही सारी तैयारी किए होते हैं और जैसे ही पैसा उनके अधिकार वाले बैंक खाते में हस्तांतरित होता है, उसे निकाल लेते हैं।

फ्रॉड करने वाले के बैंक खाते से पैसा निकलने के बाद रकम वापसी की उम्मीद बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि इसके बाद अपराधी को गिरफ्तार करके, उसकी परिसंपत्तियों से या बैंक खाते से राशि को कानूनी तरीके से वापसी की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

सूचना देने में देरी करने से बढ़ेगी मुसीबत

धोखाधड़ी का शिकार होने वाले व्यक्ति को अपने संबंधित बैंक और बैंकिंग फ्रॉड की जानकारी देने के लिए गठित वेबसाइट (नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल) पर सूचना देने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी बैंक को जानकारी मिलेगी, उसका सिस्टम उतनी ही जल्दी सक्रिय हो जाता है।

लेकिन यह ग्राहक की राशि वापसी की गारंटी नहीं है। अभी जो प्रक्रिया है, उसके मुताबिक जब धोखाधड़ी का शिकार ग्राहक बैंक को सूचना देता है तो बैंक उस बैंक को मेल करता जिसके बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की गई है। मौजूदा नियम यह है कि उक्त बैंक के संबंधित अधिकारी को 24 घंटे में ट्रांसफर किये गये बैंक खाते को जब्त करना पड़ता है और उससे राशि वापसी की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। 24 घंटे की अवधि में तो पैसा एक खाते से निकल कर कहां से कहां चला गया होता है।

बड़ी रकम की जानकारी पुलिस को देनी होगी

अगर फ्रॉड की राशि एक लाख रुपये से ज्यादा की है तो फिर उसकी जानकारी पुलिस को देनी होती है। पुलिस की जांच शुरू होने के बाद तो प्रक्रिया और लंबी खींच जाती है। तो क्या इस बारे में आगे कुछ नहीं किया जा सकेगा? इस बारे में पूछने पर आरबीआई के अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में उनके तरफ से कुछ अहम कदम उठाए जाएंगे। सभी बैंकों के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के उपयोग पर काम किया जा रहा है।

नई व्यवस्था ऐसी होगी कि बैंक ग्राहक की तरफ से एक निश्चित पोर्टल या नंबर पर सूचना देने के साथ ही उसके बैंक खाते से जिस खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है वह जब्त हो जाएगा। उससे संबंधित सूचना दूसरे बैंकों को भी जा सकेगी। इसके साथ ही यूपीआई ढांचे को भी और ज्यादा सुरक्षित बनाने की तैयारी है। सरकार के लिए यह चिंता की बात है कि यूपीआई भी फ्रॉड करने वालों का एक जरिया बन गया है।

लाइफ टाइम हाई पर शेयर, स्टॉकहोल्डर हुए मालामाल

आज भारत की स्टेड डिपॉजिटरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयर ने आज लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया। सीडीसीएल के शेयर के साथ आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के शेयर भी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इन दोनों कंपनी के शेयर की कीमत क्या है।

नई दिल्ली। शेयर बाजार में आज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयर अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि सीडीसीएलभारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी और एकमात्र लिस्टेड डिपॉजिटरी है।

आज के कारोबारी सत्र में सीडीसीएल के शेयर (CDSL Share) 1,855.90 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए थे। यह अभी तक का लाइफ टाइम हाई है। लाइफ-टाइम हाई के साथ ही कंपनी के शेयर ने नए 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर को छू लिया है। अब कंपनी के शेयर का 52-वीक हाई 1,865.40 रुपये है।

1.05 बजे सीडीसीएल के शेयर 6.84 फीसदी या 117.55 रुपये बढ़कर 1,836.15 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस

किसी भी शेयर की परफॉर्मेंस इस आधार पर तय होती है कि कंपनी ने शेयरधारकों को कितना रिटर्न दिया है। सीडीसीएल के शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले छह महीने में ही कंपनी के शेयर ने 87 फीसदी का रिटर्न दे दिया है। वहीं बीते एक साल में कंपनी के स्टॉक में लगभग 92 फीसदी की तेजी आई है। इस साल कंपनी ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर (Bonus Share) का तोहफा भी दिया था। आपको बता दें कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की वेबसाइट के मुताबिक सीडीसीएल का मार्केट कैपिटलाइजेशन 38,493.62 करोड़ रुपये है।

BSE शेयर में भी तेजी

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सेंज (BSE) के शेयरों में भी तेजी आई है। कंपनी के शेयर 10 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। 1.15 बजे कंपनी के शेयर 479.80 रुपये या 10.49 फीसदी की बढ़त के साथ 5,051.85 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। एनएसई की वेबसाइट के अनुसार बीएसई का एम-कैप 68,390.11 करोड़ रुपये है। आपको बता दें कि बीएसई के शेयर केवल एनएसई पर ट्रेड करते हैं।

जब तक ट्रूडो सत्ता में रहेंगे नहीं सुधर सकते भारत-कनाडा संबंध, सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

कनाडा और भारत के बीच के संबंध अपने संबसे निचले पायदान पर हैं। दोनों देशों के बीच के संबंध कब ठीक होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बीच एंगस रीड इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे किया है। सर्वे में इस बात पर आम सहमति नहीं बन पाई कि भारत-कनाडा संबंधों में आयी गिरावट के लिए कौन जिम्मेदार है । हालांकि अधिकांश लोगों ने माना कि ट्रूडो ही जिम्मेदार हैं।

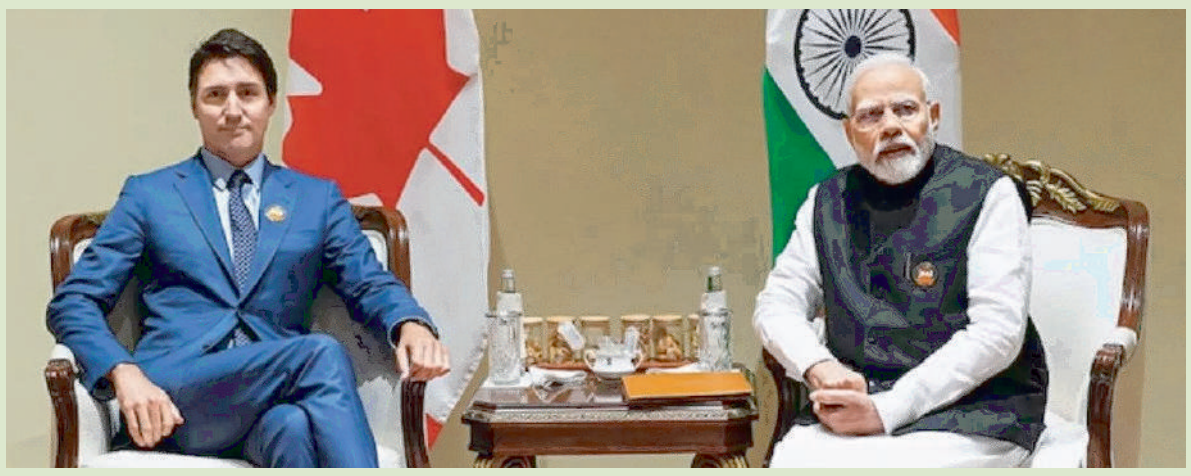

नई दिल्ली। भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक खींचतान जारी है। जस्टिन ट्रूडो सरकार के शासन में दोनों देशों के संबंध खराब हुए हैं। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 39 प्रतिशत कनाडाई मानते हैं कि जब तक ट्रूडो प्रधानमंत्री हैं, तब तक संबंधों में सुधार नहीं होगा, जबकि 34 प्रतिशत लोगों का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में भी यही मानना था।

रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

एंगस रीड इंस्टीट्यूट (एआरआइ) और एशिया पैसिफिक फाउंडेशन आफ कनाडा द्वारा किए गए सर्वेक्षण में इस बात पर आम सहमति नहीं बन पाई कि भारत-कनाडा संबंधों में आयी गिरावट के लिए कौन जिम्मेदार है। हालांकि, ज्यादातर लोगों ने इसका दोष कनाडा सरकार पर मढ़ा है।

जानिए क्या है लोगों का मानना

सर्वेक्षण के अनुसार, 39 प्रतिशत कनाडाई मानते हैं कि कनाडा अपने संबंधों को ठीक नहीं कर पा रहा है, जबकि 32 प्रतिशत लोगों का विपरीत दृष्टिकोण था तथा 29 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे निश्चित नहीं हैं।

गौरतलब है कि कनाडा में 2025 में संसदीय चुनाव होने जा रहे हैं और विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के चुनाव जीतने की प्रबल संभावना है। अगर कंजर्वेटिव जीतते हैं, तो पियरे पोलीवरे कनाडा के प्रधानमंत्री होंगे, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को फिर से बेहतर बनाने का मौका मिलेगा।

भारत और कनाडा के संबंध हुए खराब

भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। दोनों देशों के बीच रिश्तों में कड़वाहट उस समय शुरू हुई जब कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में भारत के संलिप्तता की बात कही थी। इसके बाद भारत सरकार पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाते हुए 14 अक्तूबर को पीएम ट्रूडो ने कनाडा में 5 भारतीय राजनयिकों सहित उच्चायुक्त संजय वर्मा को निष्काषित कर दिया। इसके जवाब में भारत ने कनाडा के 6 राजनयिको को निष्कासित कर दिया। इन दोनों घटनाओं की बाद से कनाडा और भारत के बीच संबंध और खराब होते चले गए हैं।

झारखंड में कड़ाके की ठंड और बारिश की संभावना: जानिए मौसम का मिजाज

इशिका मुख्य रिपोर्टर रांची झारखंड न्यूज परिवहन विशेष

झारखंड में सर्दी का असर तेजी से बढ़ने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राज्य में आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट और बारिश की संभावना जताई है। ठंडी हवाओं और हल्की बारिश से झारखंड के कई इलाकों में मौसम सर्द और सुहावना हो जाएगा।

तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान*

मौसम केंद्र रांची के अनुसार, अगले दो दिनों में झारखंड के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। इससे राज्य के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। हालांकि, इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने का भी अनुमान है।

8 और 9 दिसंबर को बारिश का दौर*

मौसम विभाग ने बताया कि झारखंड के उत्तर-पश्चिम और पश्चिमी इलाकों में 8 दिसंबर को हल्की बारिश होने की संभावना है। यह बारिश 9 दिसंबर को भी जारी रह सकती है।

हालांकि, बारिश का असर पूरे राज्य में नहीं बल्कि केवल कुछ जिलों तक सीमित रहेगा।

10 दिसंबर से आसमान होगा साफ*

बारिश के बाद 10 दिसंबर से झारखंड में मौसम साफ होने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी जा सकती है।

रांची में बारिश का अनुमान*

राजधानी रांची में 8 दिसंबर को आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि 9 दिसंबर को हल्की बारिश हो सकती है। बारिश और बादल छाए रहने के दौरान रांची का न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है।

किन इलाकों में हो सकती है बारिश?*

झारखंड के इन जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है:

- पलामू
- गढ़वा
- चतरा
- कोडरमा
- लातेहार
- लोहरदगा
- रांची

कोई चेतावनी नहीं जारी*

मौसम विभाग ने झारखंड में बारिश और ठंड को लेकर कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है। हालांकि, ठंड से बचने के लिए सावधानियां बरतने और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है।

झारखंड में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। ठंड और हल्की बारिश से जहां सर्दी का अहसास बढ़ेगा, वहीं मौसम के बदलते रुख के साथ सतर्क रहने की भी जरूरत है। खासतौर पर बारिश के दौरान ठंड से बचाव के उपाय जरूर करें।

धार्मिक स्थलों पर विवादों को सुलझाने में न्यायपालिका

प्रियंका सौरभ

धार्मिक विवादों में न्यायिक फैसले अक्सर राजनीतिक लामबंदी के उपकरण बन जाते हैं, जो न्यायपालिका की तटस्थता बनाए रखने की क्षमता को चुनौती देते हैं। संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के साथ धार्मिक अधिकारों को संतुलित करना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है, खासकर जब निर्णयों को एक समुदाय के पक्ष में माना जाता है। विवादित धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों को अनुमति देना अधिनियम के मूल सिद्धांत को कमजोर करता है, जिससे पूजा स्थलों को लेकर भविष्य में संघर्षों के लिए एक मिसाल क़ायम होती है। संवैधानिक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने और धर्मनिरपेक्षता की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता है। धार्मिक स्थलों पर विवादों को सुलझाने में न्यायपालिका को संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव सर्वोपरि रहे। पूजा स्थल अधिनियम के सिद्धांतों को सुदृढ़ करके, समय पर और निष्पक्ष निर्णय देकर और संघर्ष समाधान तंत्र को बढ़ावा देकर न्यायपालिका जनता का विश्वास बना सकती है और ऐतिहासिक शिकायतों को सामाजिक शांति को बाधित करने से रोक सकती है। भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने की रक्षा करने वाला भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण इसके विविध, बहुलवादी समाज में एकता बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

न्यायपालिका भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता, समानता और न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करते हुए धार्मिक स्थलों पर विवादों को सुलझाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालाँकि, यह कार्य ऐतिहासिक दावों को समकालीन अधिकारों के साथ संतुलित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, भावनात्मक संवेदनशीलता को सम्बोधित करने और पूजा स्थल अधिनियम, 1991 जैसे कानूनी ढाँचों का पालन सुनिश्चित करने जैसी चुनौतियों से भरा है। ये जटिलताएँ संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए एक सावधान और निष्पक्ष दृष्टिकोण की माँग करती हैं। अगर किसी देश को नष्ट करना है तो उसकी सांस्कृतिक पहचान को खत्म कर दो। देश अपने आप नष्ट हो जाएगा। भारत पर हमला करने वाले विदेशी आक्रांताओं ने यही किया। इस्लामी आक्रांताओं ने न सिर्फ धन-संपदा लूटी बल्कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मंदिरों और धार्मिक स्थलों को तोड़ कर मस्जिदें बना दीं। अंग्रेजों का लक्ष्य भी भारत को कमजोर बनाकर यहां के संसाधनों का दोहन करना था। इसलिए उन्होंने भी भारत की सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास किए। आक्रांताओं द्वारा नष्ट किए गए धार्मिक स्थल सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं हैं।

एक प्राचीन सभ्यता के तौर पर इनके बिना भारत की पहचान पूर्ण नहीं होती है। अयोध्या, काशी और मथुरा इसके कुछ उदाहरण हैं। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद आज सनातन संस्कृति का पुनरुद्धार हो रहा है। काशी, मथुरा,संभल और अजमेर दरगाह मामले में साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर भारत की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीकों को हासिल करने का प्रयास हो रहा है। धार्मिक स्थलों पर विवादों को सम्बोधित करने में न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियाँ जैसे कानूनी ढाँचे में अस्पष्टता। हालाँकि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 का उद्देश्य धार्मिक स्थलों की 1947 वाली स्थिति को स्थिर करना है, लेकिन इसके प्रावधान अलग-अलग व्याख्याओं के लिए जगह छोड़ते हैं, जिससे इसका प्रवर्तन कमज़ोर होता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद जैसे मुकदमों को अनुमति दी, अधिनियम की व्याख्या धार्मिक चरित्र निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण की अनुमति देने के रूप में की। सदियों पुरानी शिकायतों पर दोबारा ग़ौर करने से सांप्रदायिक तनाव बढ़ने, सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होने और सामाजिक एकता को नुक़सान पहुँचने का ख़तरा रहता है। धार्मिक विवादों में न्यायिक फैसले अक्सर राजनीतिक लामबंदी के उपकरण बन जाते हैं, जो न्यायपालिका की तटस्थता बनाए रखने की क्षमता को चुनौती देते हैं।

संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के साथ धार्मिक अधिकारों को संतुलित करना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है, खासकर जब निर्णयों को एक समुदाय के पक्ष में माना जाता है। विवादित धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों को अनुमति देना अधिनियम के मूल सिद्धांत को कमजोर करता है, जिससे पूजा स्थलों को लेकर भविष्य में संघर्षों के लिए एक मिसाल क़ायम होती है। संवैधानिक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने और धर्मनिरपेक्षता की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता है। न्यायपालिका अक्सर संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धी धार्मिक दावों को संतुलित करती है (अनुच्छेद 25-28)। उदाहरण के लिए: एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में, सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान की एक बुनियादी विशेषता घोषित किया, जिसने धार्मिक मामलों में राज्य की निष्पक्षता को मज़बूत किया। यह सुनिश्चित करता है कि धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25) दूसरों के अधिकारों या सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करती है। न्यायालय ऐतिहासिक अभिलेखों और साक्ष्यों के माध्यम से धार्मिक स्थलों पर विवादों की जांच करते हैं, धार्मिक भावनाओं पर संवैधानिक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अयोध्या विवाद (एम. सिद्दीक बनाम महंत सुरेश दास, 2019) में, सर्वोच्च न्यायालय ने निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रभावित पक्ष को वैकल्पिक भूमि आवंटित करते हुए संतुलित फ़ैसला देने के लिए ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों पर भरोसा किया। न्यायपालिका संवैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सांस्कृतिक या विरासत स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त धार्मिक संरचनाओं की सुरक्षा करती है।

अरुणा रॉय बनाम भारत संघ (2002) में, न्यायालय ने अनुच्छेद 51ए (एफ) के तहत समग्र संस्कृति को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया, जो विरासत धार्मिक स्थलों पर विवादों में प्रासंगिक है। न्यायालय प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के साथ धार्मिक विवादों का निपटारा करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी पक्षों को बिना किसी पूर्वाग्रह के सुना जाए। ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद में न्यायपालिका ने साक्ष्यों के संग्रह और मूल्यांकन में प्रक्रियागत अनुपालन पर ज़ोर दिया है, जिससे निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों को सुनिश्चित किया जा सके। धार्मिक स्थलों पर विवादों को सुलझाने में न्यायपालिका को संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव सर्वोपरि रहे। पूजा स्थल अधिनियम के सिद्धांतों को सुदृढ़ करके, समय पर और निष्पक्ष निर्णय देकर और संघर्ष समाधान तंत्र को बढ़ावा देकर न्यायपालिका जनता का विश्वास बना सकती है और ऐतिहासिक शिकायतों को सामाजिक शांति को बाधित करने से रोक सकती है। भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने की रक्षा करने वाला भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण इसके विविध, बहुलवादी समाज में एकता बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

हेमन्त सोरेन का मंत्रि मडल का गठन ,11 मंत्री ने ली शपथ

झारखंड विधानसभा में 20 वर्षों से ओडिय़ा को जगह नहीं, मनोनयन भी नहीं

कार्तिक परिच्छा, स्टेट हेड, झारखंड

रांची, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने स्टीफन मरांडी को झारखंड विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर एवं राज्य मंत्रिपरिषद में शामिल 11 सदस्यों को पद और गोपनीयता की आज शपथ दिलाई।

जहां विधायक राधाकृष्ण किशोर, दीपक बिरुवा, चमरा लिंडा, संजय प्रसाद यादव, रामदास सोरेन, इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, दीपिका पांडेय सिंह, योगेंद्र प्रसाद, सुदिव्य कुमार एवं शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में शपथ राज्यपाल के समक्ष ली । झारखंड राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार एवं मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मंत्रिपरिषद में शामिल सभी मंत्रीगणों को

बधाई और शुभकामनाएं दी।

इनमें से छह विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा, चार कांग्रेस के और एक राष्ट्रीय जनता दल का विधायक है। हेमंत कैबिनेट में दो महिलाओं को भी जगह दी गई है। सर्वाधिक उम्र दराज 66 वर्षिय राधाकृष्ण किशोर है।

आश्चर्य की बात यह है कि झारखंड गठन के साथ ओड़िआ भाषी इलाका सरायकेला खरसावां को पुनः ओडिशा को लौटाने की बात ओडिशा सदन एवं लोकसभा को काफी गर्म किया था।आज झारखंड गठन के बाद केवल दिनेश षाड़ंगी को ही मंत्रालय मिला था वह भीज्ञ 20 वर्ष पहले।विधानसभा में अंग्रेजों का मनोनयन खत्म हुआ पर आजतक ओडिया मनोनयन हो नहीं पाया । आज झारखंडी ओड़िया किस प्रकार उपेक्षित है , किस श्रेणी के नागरिक हैं ,देश आजादी के बाद 562 राजबाड़े का एक काला अध्याय है लोकतंत्र में 2 प्रिन्सली स्टेट्स सरायकेला , खरसावां अजीबो-गरीब राजनीतिक

दास्तां। विलय दस्तावेज में उत्थान के जगह पतन की दिशा में यहां मूल ओडिया भाषी। सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, भाषा , संस्कृति आर्थिक स्थिति बद से बद्तर होने का कारणज्ञ कारण इनकी प्रतिनिधित्व ही समाप्त है षड्यंत्रकारियों के कारण बिहार व झारखंड में।

राजभवन के अशोक उद्यान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कई सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, वरीय अधिकारी तथा कई गणमान्य आज मौजूद थे ।

विदित हो कि हेमन्त सोरेन ने 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके उपरांत आज उन्होंने अपने मंत्रिपरिषद का गठन किया।

कुर्सी के लिए रुठ जाते नेता?

खाली कुर्सी के लिए रुठ जाते नेता,
ऐसे मांगते विभाग जैसे कोई क्रेता।
एक-दूजे को फूटी आँखों ना सुहाते,
मजबूरी में गलबहियाँ कर बैठ जाते!
सत्ता में खुद को भागीदार बना पाते।

खाली कुर्सी के लिए रुठ जाते नेता,
ऐसे मांगते विभाग जैसे कोई क्रेता।
कोई किसी के पक्ष में कोई ख़लिाफ,
नहीं पता था बहुमत का भी है सैलाब!
बैठा जो विपक्ष में करता रहा विलाप।

खाली कुर्सी के लिए रुठ जाते नेता,
ऐसे मांगते विभाग जैसे कोई क्रेता।
देखो मनाया गया शिंदे को बार-बार,
वे मुंबई से सतारा भले करते रहे वार!
बड़े निर्णय से बचते रहे क्यों? सरकार।

खाली कुर्सी के लिए रुठ जाते नेता,
ऐसे मांगते विभाग जैसे कोई क्रेता।
अजित दादा को सत्ता से बड़ा प्यार,
भाजपा से नहीं इनकी कोई भी रार!
कभी-न-कभी तो लगेगी ही नैया पार।

खाली कुर्सी के लिए रुठ जाते नेता,
ऐसे मांगते विभाग जैसे कोई क्रेता।
दादा तो बरसों से कर रहे हैं इंतजार!
मुख्यमंत्री बनने का है इनका विचार,
पता नहीं इन्हें कब मिलेगा ये उपहार?

संजय एम. तराणेकर

राजस्थान में सर्दी की छुट्टियों का नया नियम: अब ठंड के तेवर तय करेंगे अवकाश

इशिका मुख्य रिपोर्टर रांची झारखंड न्यूज परिवहन विशेष

राजस्थान में सर्दियों की छुट्टियों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की है कि अब सर्दी की छुट्टियां तय तारीखों पर नहीं, बल्कि ठंड की तीव्रता के आधार पर होंगी। यह कदम बच्चों की पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाने और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है।

सर्दियों की छुट्टियां: पुरानी और नई व्यवस्था*

अब तक राजस्थान में सर्दियों की छुट्टियां शैक्षिक कैलेंडर के तहत पहले से तय होती थीं, जो आमतौर पर 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक होती थीं। चाहे सर्दी पड़ रही हो या नहीं, ये अवकाश घोषित किए जाते थे। लेकिन इस व्यवस्था में कई समस्याएं सामने आ रही थीं।

- ठंड न होने पर भी छुट्टियां होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी।
- अवकाश के दौरान स्कूलों में अनावश्यक रुकावटें होती थीं।

अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सर्दी की छुट्टियां केवल कड़ाके की ठंड के दौरान ही घोषित हों। यदि सर्दी देर से शुरू होती है, तो छुट्टियां भी उसी के अनुसार शुरू होंगी।

2024-25 कैलेंडर में बदलाव की संभावना*

राजस्थान शिक्षा विभाग ने इस साल 28 जुलाई को 2024-25 के लिए वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था। इसमें 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियां निर्धारित थीं। लेकिन मंत्री के नए फरमान के बाद संभावना जताई जा रही है कि इस कैलेंडर में बदलाव किया जाएगा।

मदन दिलावर ने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग भविष्य में शीतकालीन अवकाश के लिए नए तरीके अपनाएगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो।

शीतकालीन अवकाश का महत्व

सर्दी की छुट्टियां छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं।

- छात्रों को यह समय पढ़ाई के साथ-साथ आराम और अन्य गतिविधियों के लिए मिलता है।
- शिक्षकों को भी यह समय नए शैक्षणिक सत्र की योजना बनाने का अवसर प्रदान करता है।

हालांकि, तय तारीखों पर छुट्टियां घोषित करने से कई बार ऐसे समय में स्कूल बंद हो जाते थे, जब मौसम अनुकूल होता था और पढ़ाई जारी रह सकती थी।

सरकार का उद्देश्य*

सरकार इस नई व्यवस्था के जरिए शिक्षा प्रणाली में सुधार और पढ़ाई के लिए अधिक अनुकूल माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि मौसम आधारित अवकाश से बच्चों को ठंड से राहत मिलेगी और साथ ही उनकी पढ़ाई का समय भी बचाया जा सकेगा।

छात्रों और अभिभावकों की प्रतिक्रिया*

छात्र और अभिभावक इस फैसले को सकारात्मक रूप से देख रहे हैं। उनका मानना है कि यह बदलाव बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहतर होगा।

शीतकालीन अवकाश में बदलाव राजस्थान में शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह न केवल छात्रों को मौसम के अनुसार राहत प्रदान करेगा, बल्कि पढ़ाई में भी नियमितता बनाए रखेगा। शिक्षा विभाग से इस बदलाव के तहत नए कैलेंडर की जल्द घोषणा की उम्मीद की जा रही है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023